सुबह सवेरे

A Daily News Magazine
इंदौर
शनिवार, 22 फरवरी, 2025

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 10 अंक 143, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

चीन का सामना करने के लिए भारतीय सेना अंडरग्राउंड युद्ध अपनाए

ले.ज. एच.एस. पनाग (रि.)

ब्रिटेन के अखबार 'फाइनेंशियल टाइम्स' में 30 जनवरी को छपी एक रिपोर्ट बताती है कि चीन बीजिंग में दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री कमांड सेंटर बना रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय 'पेंटागन' से 10 गुना बड़े आकार में 1500 एकड़ में फैले इस भूमिगत चीनी कमांड सेंटर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि परमाणु युद्ध समेत किसी भी युद्ध के दौरान चीन के पूरे सैन्य नेतृत्व सहित राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो सेंट्रल मिलिटरी कमीशन के अध्यक्ष भी हैं, वहां सुरक्षित रह सकें।

इस कमांड सेंटर को भूमिगत युद्ध के मामले में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के सिद्धांत के अनुरूप बनाया जा रहा है। इस तरह के युद्ध में प्रमुख कमांड, ऑपरेशन, और साजोसामान के लिए भूमिगत सुरक्षा की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है। यहां यह कहने की जरूरत नहीं है कि इन सबकी सुरक्षा के लिए विमान-रोधी मिसाइलों, ड्रोन, इलेक्ट्रोनिक तथा साइबर युद्ध में काम आने वाले कवचों आदि का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

भारतीय सेना को पहाड़ी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भूमिगत युद्ध की रणनीति अपनानी चाहिए ताकि विमानों, मिसाइलों, और ड्रोन से गिराए जाने वाले पीजीएम के मामले में चीन की बढ़त का जवाब दिया जा सके। पिछले 25 वर्षों में युद्धक्षेत्र ज्यादा पारदर्शी हो गया है। सैन्य मामले में भारत और चीन के बीच अंतर मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक तथा साइबर युद्ध के क्षेत्र में, और विमानों तथा जमीन से दागे जाने वाले पीजीएम की क्षमता और संख्या के मामले में है। परमाणु हथियार भारत को निर्णायक हार या अपनी जमीन के बड़े नुकसान से तो बचा सकते हैं लेकिन सीमित युद्ध या इससे निचले स्तर के ऑपरेशनों के मामले में यह अंतर निर्णायक साबित हो सकता है। दुश्मन पर सीधा हमला न करके भी हमारी सुरक्षा व्यवस्था को और कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम को तथा साजोसामान को भी तैनात विमानों या जमीन से मार करने वाले पीजीएम और ड्रोन के साथ-साथ इलेक्ट्रोनिक तथा साइबर आक्रमणों के जरिए नष्ट कर सकता है। फिलहाल, परिमाण और गुणवत्ता के लिहाज से 'स्टैंडऑफ' हमलों का जवाब विमान-रोधी तोपों/मिसाइलों, ड्रोनों और इलेक्ट्रोनिक/साइबर युद्ध के जरिए देने की भारत की क्षमता चीन की इस क्षमता के मामले में करीब एक दशक पीछे है।

हमारे पहाड़ी तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों की प्रतिरक्षा व्यवस्था छोटे हथियारों, गैर-पीजीएम तोपों तथा विमानों से होने वाले हमलों से बचाव के लिहाज से तैयार की गई है। अनिर्देशित तोपों, मिसाइलों आदि की प्रभावशीलता उलटी ढलान, पहाड़ी चोटियों, और बदलते मौसम के कारण घटती है। सेना की एक कंपनी की सुरक्षा में स्थित क्षेत्र में करीब 50 बंकर होते हैं। करगिल युद्ध में एक कंपनी की सुरक्षा में स्थित क्षेत्र के लिए तोपों के 5000 से लेकर 10 हजार गोले तक दागे गए और इनके साथ 'फर्स्ट जेनरेशन' वाले विमानों से पीजीएम दागे गए। लेकिन हरेक मामले में दुश्मन करीबी लड़ाई लड़ने के लिए जीवित बचे रहे। हरेक बंकर या पिलबॉक्स चार-पांच फुट गहरा होता है, जिसकी दीवारें आरसीसी की होती हैं जिनके साथ स्टील की चादर मढ़ी होती है, और उनमें जमीन से करीब एक फुट ऊपर लूपहोल बने होते हैं फायरिंग करने के लिए। उसके ऊपर तीन फुट ऊंची मिट्टी जमा होती है ताकि विस्फोटों को बेअसर किया जा सके। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 'बचाव पक्ष के वर्चस्व' को बेअसर करने और प्रतिकूलताओं से बचने के लिए पीएलए 'करीबी लड़ाई' में नहीं उलझना चाहेगी। वह पीजीएम, ड्रोन, और साइबर/इलेक्ट्रोनिक साधनों के इस्तेमाल से हमला करेगी। बचाव पक्ष को ध्वस्त करने के बाद करीबी लड़ाई बाकी बचे हुए को पोंछ डालने भर के लिए होगी। प्रत्यक्ष हमला न करते हुए सजा देने की कार्रवाई के रूप में चौकियों और साजोसामान के अड्डों को नष्ट किया जाएगा। प्रतिरक्षा के स्थायी ठिकानों और अड्डों को बचाने का एकमात्र उपाय भूमिगत या सुरंगों वाली युद्धकला को अपनाना है।

भारतीय सेना के पास भूमिगत युद्ध लड़ने का कोई औपचारिक सिद्धांत या अनुभव नहीं है। लेकिन अमेरिकी सेना के पास इसका एक सिद्धांत है। लेकिन पुराने युद्धक्षेत्रों में अनुभव से मिलने वाला बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है। वियतनाम, दक्षिण कोरिया, और जापान जैसे मित्र देशों को भूमिगत सुरंगों वाली लड़ाई का काफी अनुभव है। गाज़ा में जो सुरंगें हैं उनका ब्योरा अच्छी तरह से रखा गया है, और यूक्रेन को पीजीएम/ड्रोन से बचाव का व्यापक अनुभव हासिल है। भारत के सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को सुरंगों का निर्माण करने का गहरा अनुभव हासिल है। पहाड़ी तथा ऊंचाई वाले क्षेत्र सुरंगों वाली लड़ाई के लिए बिलकुल उपयुक्त होते हैं क्योंकि वे प्रवेश करने के लिए ऊर्ध्वाधार (वर्टिकल) और क्षैतिज (लेटरल), दोनों तरह के द्वार उपलब्ध कराते हैं।

भारतीय सेना को भूमिगत युद्धकला का लाभ उठाने के बारे में विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। एक अध्ययन दल एक ऐसा मैनुअल तैयार करे जिसमें यह बताया जाए कि भूमिगत युद्ध में प्रतिरक्षा का निर्माण कैसे करें और उसका डिजाइन क्या हो, और इस युद्ध को 'कैसे लड़ें।' इसके लिए सैनिक स्कूलों में वास्तविक मॉडलों के साथ गहन प्रशिक्षण दिया जाए। भारतीय सेना के इंजीनियर कोर और बीआरओ को वास्तविक निर्माणों की ज़िम्मेदारी सौंपी जाए। इंडो-टिबेटन बॉर्डर पुलिस (आइटीबीपी) की चौकियों को भी भूमिगत युद्ध में प्रतिरक्षा के लिहाज से स्थापित किया जाए। युद्ध के दौरान आगे बढ़ रही सेना इन चौकियों का लाभ उठा सकती है।

गाज़ा में सुरंगों की अनुमानित लागत 1 अरब डॉलर यानी 8,700 करोड़ रुपये है। मेरे विचार से इस बजट के तहत पूर्वी लद्दाख में हमारी प्रतिरक्षा के सभी साधन, और ऑपरेशन तथा साजोसामान से संबंधित सभी ठिकानों को भूमिगत किया जा सकता है। उत्तर-पूर्व के लिए भी ऐसी ही परियोजना की लागत इससे दोगुना ज्यादा होगी। पीजीएम बहुत महंगे होते हैं और विमान-रोधी/मिसाइल/ड्रोन पर आधारित कवच बनाने की लागत और बड़ी होगी। अगर यह मान कर चलें कि विमान-रोधी एस-400/ मिसाइल/ड्रोन सिस्टम पर आधारित पांच रेजीमेंट (40 लाउंचरों) के लिए 5.5 अरब डॉलर खर्च किए गए, तो उत्तरी सीमा के लिए भूमिगत प्रतिरक्षा व्यवस्था का निर्माण लागत-लाभ के अनुपात के लिहाज से काफी लाभकारी होगा। उपयुक्त समय के अंदर इस परियोजना को नियंत्रण रेखा की प्रतिरक्षा और मैदानी इलाकों में स्थायी प्रतिरक्षा व्यवस्था के लिए भी लागू किया जा सकता है।

युद्धों का इतिहास बताता है कि संसाधनों तथा टेक्नोलॉजी के मामलों में असमानता को बेअसर करने के लिए भूमिगत युद्ध का इस्तेमाल में किया जाता रहा है। भारतीय सेना इस तथ्य की अनदेखी करेगी तो अपना ही नुकसान करेगी।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करना है, तो आरंभ जन से ही शुरू होता है: मोदी

● स्वामी विवेकानंद ने कहा था-मेरे पास 100 लीडर्स हों तो देश को नंबर वन बना सकता हूं

● पीएम बोले-किसी भी देश के निर्माण के लिए वहां के व्यक्ति का विकास जरूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के भारत मंडपम में एसओयूएल (स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप) कॉन्क्लेव के पहले एडीशन का इनॉगरेशन किया। प्रधानमंत्री ने कहा- किसी भी देश के निर्माण के लिए वहां के व्यक्ति यानी नागरिकों का विकास जरूरी है। पीएम ने कहा- किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करना है, तो आरंभ जन से ही शुरू होता है। हर क्षेत्र में बेहतरीन लीडर्स का विकास बहुत जरूरी है। यह समय की मांग है। इसलिए एसओयूएल की स्थापना 'विकसित भारत' की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है। उन्होंने कहा- स्वामी विवेकानंद जी भारत को गुलामी से बाहर निकालकर बदलाव लाना चाहते थे। उनका विश्वास था कि अगर 100 लीडर उनके पास हों, तो वह भारत को आजादी ही नहीं, बल्कि दुनिया का नंबर वन देश बना सकते हैं। इसी मंत्र को लेकर हम सबको आगे बढ़ना है। एसओयूएल में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे भी शामिल हुए हैं। उनके आने पर पीएम मोदी ने कहा- भूटान के राजा का आज जन्मदिन होना और हमारे यहां ये अवसर होना। ये अपने आप में सुखद संयोग हैं। भूटान के पीएम को यहां भेजने में बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

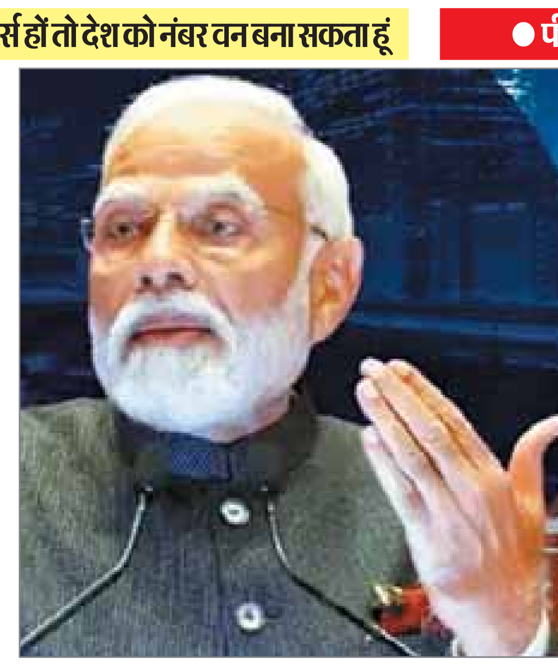

- **हमें हर मोर्चे पर बेहतर नेतृत्व की है जरूरत** – पीएम ने कहा– आज हर भारतीय 21वीं सदी के 'विकसित भारत' के लिए दिन–रात काम कर रहा है। ऐसे 140 करोड़ देश में हर सेक्टर में, हर कार्यक्षेत्र में, जीवन के हर आधार में हमें उत्तम से उत्तम नेतृत्व की आवश्यकता है। कुछ आयोजन ऐसे होते हैं, तो हृदय के बहुत करीब होते हैं और आज का ये प्रोग्राम भी ऐसा ही है। उन्होंने कहा– किसी भी देश को प्रगति करने के लिए न केवल प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, बल्कि मानव संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। 21वीं सदी में हमें ऐसे संसाधनों की आवश्यकता है जो नवाचार को बढ़ावा दे सकें और कौशल को प्रभावी ढंग से चैनल कर सकें। हमें वैज्ञानिक रूप से नेतृत्व विकास में तेजी लानी चाहिए।
- **भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है – पीएम** ने कहा– भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, और यह गति हर क्षेत्र में हो रही है। इस वृद्धि को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए हमें विश्व स्तरीय नेताओं की आवश्यकता है। ये संस्थाएं इस परिवर्तन में एक गेम–चेंजर हो सकती हैं।
- **हमें ग्लोबल थिंकिंग, लोकल अप–ब्रिंगिंग के साथ बढ़ना है** – प्रधानमंत्री ने कहा– आने वाले समय में जब हम डिप्लोमेसी से टेक इनोवेशन तक एक नई लीडरशिप को आगे बढ़ाएंगे तो सभी क्षेत्रों में भारत का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। यानी एक तरह से भारत का पूरा विजन और भविष्य एक मजबूत नेतृत्व पीढ़ी पर निर्भर है, इसलिए हमें ग्लोबल थिंकिंग और लोकल अप–ब्रिंगिंग के साथ आगे बढ़ना है।
- **दुनिया से प्रतिस्पर्धा के लिए हमें स्मार्ट लीडर्स चाहिए** – हमें ऐसे व्यक्तियों को तैयार करने की आवश्यकता है जो भारतीय मानसिकता के साथ अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को समझते हों। इन नेताओं को रणनीतिक निर्णय लेने, संकट प्रबंधन में पारंगत होना चाहिए।

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

काट मन के घाट ले कर जा चुका
शेष बस प्रतिबिम्ब मेरा रह गया है
बह रहा मुझ में नदी जैसा
तुम्हारे प्रेम का जल!
इक छुवन से कट गया पत्थर
इक विनय पर झुक गया अम्बर
अजनबी सूने नदी तट पर
प्यास मेरी थम गयी आकर
और फिर तबसे
रह रहा मुझमें सदी जैसा
तुम्हारे प्रेम का पल!
डूबकर भी प्यास में हूँ मैं
पा लिया पर आस में हूँ मैं
दूर तुम,पर पास में हूँ मैं
शून्य के आभास में हूँ मैं
क्या पता कैसे?
मिल नहीं पाया मुझे अब तक
जटिल इस प्रेम का हल!
तुम अगर होते बदल जाता
सत्य में हर स्वप्न ढल जाता
दर्द का काँटा निकल जाता
साधना का कर्म फल जाता
खो गए हो तो,
बन गया प्रारब्ध अब मेरा
हमारे प्रेम का कल!

– अंकिता सिंह

महाकुंभ आने-जाने के दौरान तीन हादसे, 16 की मौत

पटना लौट रही कार ट्रक में घुसी, वाराणसी में जीप खड़े ट्रक से टकराई

नई दिल्ली (एजेंसी)। महाकुंभ से जुड़े तीन हादसों में 16 लोगों की मौत हो गई। इनमें से दो हादसे उत्तर प्रदेश, तो एक हादसा बिहार में हुआ। दो एक्सीडेंट में लोग महाकुंभ में स्नान करके लौट रहे थे, जबकि एक परिवार डुबकी लगाने जा रहा था। बिहार के भोजपुर में महाकुंभ से लौट रही कार ट्रक के पीछे घुस गई। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इनमें से चार लोग एक ही परिवार के थे। वहीं, वाराणसी में प्रयागराज हाईवे पर श्रद्धालुओं की कार खड़े ट्रक से टकरा गई। ये लोग स्नान करने जा रहे थे। इधर, यूपी के ही गाजीपुर में महाकुंभ से लौटते हुए एक कार वाराणसी-गोरखपुर हाईवे पर खड़े ट्रॉले से टकरा गई। इसमें 4 की मौत हो गई।

मृतकों में पूर्णिया (बिहार) के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की भांजी भी थीं।

- **भोजपुर में कार ट्रक में घुसी:** बिहार के भोजपुर में महाकुंभ से लौट रहे 6 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मरने वालों में एक परिवार के 4 लोग (दंपति, बेटा और भतीजी) थे। घटना शुक्रवार सुबह पटना से 40 किमी पहले आरा–मोहनिया नेशनल हाईवे पर हुई।
- **वाराणसी में खड़े ट्रक से कार टकराई:** वाराणसी–प्रयागराज हाईवे पर महाकुंभ जा रहे कर्नाटक के श्रद्धालुओं की कार खड़े ट्रक से टकरा गई। पति–पत्नी समेत 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि महिला का सिर कटकर सड़क पर जा गिरा।
- **महाकुंभ से लौटते हुए हादसा, 4 की जान गई:** यूपी के गाजीपुर में गुरुवार रात सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की भांजी डॉ. सोनी यादव, उनकी बुआ गायत्री देवी भी शामिल हैं।

प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप उपलब्ध कराने से प्रदेश के उज्जवल भविष्य की संभावनाएं अधिक सशक्त होंगी : मुख्यमंत्री

प्रत्येक विद्यार्थी 25-25 हजार की राशि से अपनी पसंद से ले सकेंगे लैपटॉप

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि परिवार परंपरा में मां द्वारा अपने बच्चों को पुष्पित, पोषित करने में प्राप्त आनंद का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार प्रदेश के प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान करने से जो आनंद प्राप्त हो रहा है, वह वर्णनातीत है, यह जीवन भर याद रहने वाली अनुभूति है। जैसे परिवार में सदस्यों का सभी संसाधनों पर अधिकार होता है, उसी प्रकार राज्य सरकार के सभी संसाधनों पर समाज के कमजोर से कमजोर तबके का अधिकार है। मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान करने से उनकी प्रतिभा निखरेगी, जिससे प्रदेश के उज्जवल भविष्य की संभावनाएं अधिक सशक्त होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश के 89 हजार 710 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप लेने के लिए 224 करोड़ की राशि अंतरित करने के लिए प्रशासन अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सिंगल क्लिक से विद्यार्थियों के खातों में राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्यार्थियों से कहा कि उन्हें उपलब्ध कराई जा रही 25-25 हजार रूपए राशि का उपयोग लैपटॉप क्रय में ही किया जाए। विद्यार्थी अपनी पसंद के अनुसार, अपनी इच्छानुसार स्थान से लैपटॉप लें और लैपटॉप खरीदने की रसीद अपनी शाला में आवश्यक रूप से जमा कराएं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित तथा माँ सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को पौध भेंट कर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्यार्थियों से संवाद किया तथा अपने उद्बोधन के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित भी किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग, भोपाल के प्रभारी तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य कुार काश्यप, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, भोपाल महापौर श्रीमती मालती राय, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, श्री रवीन्द्र यती सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, विद्यार्थी और अभिभावक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत में विद्यमान गुरुकुल परंपरा जातियों और वर्ग भेद से मुक्त थी। सभी को समान रूप से सभी व्यवस्थाओं के लिए अधिकार देकर और प्रतिभाओं को निखार कर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता था। इसी की निरंतरता में आज प्रदान किया जा रहे लैपटॉप से विद्यार्थियों को अध्ययन तकनीक का उपयोग करते हुए ज्ञानार्जन और कौशल विकास में मदद मिलेगी। विद्यार्थियों में आगे बढ़ने के और नवाचार करने के लिए आत्मविश्वास विकसित होगा।

सीएम ने पूछा- नेता नहीं बनना चाहती हो?

दमोह की मोनिका साहू ने कहा- मैंने प्रदेश में 5वां रैंक हासिल किया है। मैं आईएएस बनना चाहती हूं। इस पर सीएम बोले- नेता नहीं बनना चाहती हो? तो सभी स्टूडेंट मुस्कुराने लगे।

भोपाल के स्टूडेंट प्रशांत राजपूत ने कहा- मेरे पिताजी की बंसल अस्पताल के सामने चाय की दुकान है। माताजी गृहिणी हैं। लैपटॉप मिलने के बाद मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाऊंगा। वहीं, मुरैना की स्नेहा त्यागी बोली- अब यूपीएससी की तैयारी करनी है। लैपटॉप से काफी मदद मिलेगी।

सीएम ने पूछा- हमें कब से जानती हो? तो स्नेहा बोली- एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में आपके हाथों 50 हजार रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। भोपाल के प्रशांत ने कहा- पिता की चाय की दुकान है। लैपटॉप मिलने से हम खुश हैं।

स्टूडेंट बोले- विश्वास था, लैपटॉप मिलेगा

वहीं, जय जाट ने कहा- लैपटॉप के लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ा लेकिन मुझे विश्वास था कि ये जरूर मिलेगा। मेरे पिताजी पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। मैं इनकम टैक्स विभाग में अधिकारी बनना चाहता हूं।भोपाल के पुष्पेंद्र राजपूत बोले- मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो मैंने इसे खरीद लिया। अब पैसे आ जाएंगे तो चुका दूंगा।

नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के वीडियो हटाने के निर्देश

● रेलवे ने एक्स को नोटिस जारी कर 288 लिंक हटाने को कहा, 18 लोगों की मौत हुई थी

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन रेलवे ने एक फरमान जरूर जारी किया है। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस जारी कर 288 वीडियोज लिंक हटाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने 17 फरवरी को यह नोटिस भेजा था और एक्स को 36 घंटे में घटना से जुडे सभी वीडियो लिंक हटाने का

निर्देश दिया था। मंत्रालय के नोटिस में कहा गया कि यह नैतिकता के खिलाफ तो है ही, साथ ही एक्स के कंटेंट पॉलिसी के भी खिलाफ है। इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने से कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। अभी ट्रेनों में भारी भीड़ है, इसे देखते हुए रेलवे के ऑपरेशन को प्रभावित कर सकती है। दिसंबर में प्रत्यक्ष रूप से वीडियो हटाने का अधिकार मिलने के बाद कंटेंट को लेकर यह मंत्रालय की पहली बड़ी कार्रवाई है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 22°c
न्यूनतम 16°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ शनिवार,22 फरवरी 2025

> जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
>
> चाणक्य नीति

संभल दंगों की दुबई में रची गई थी साजिश

डी-कंपनी की थी तैयारी, विदेशी कारतूस का हुआ इस्तेमाल

संभल (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा को लेकर यूपी पुलिस ने गुरुवार को 400 पेज की चार्जशीट फाइल की। इसमें बताया गया है कि किस तरह से दुबई में रहने वाला शारिक साठा हिंसा का मास्टरमाइंड था। शारिक साठा अभी दुबई में है और उसका संबंध डी कंपनी से भी है। चार्जशीट में बताया गया कि इस हिंसा के पीछे डी कंपनी का हाथ था। पुलिस ने कहा कि शारिक साठा का दिल्ली में एक गिरोह था और इसने दिल्ली-एनसीआर में

300 से अधिक गाड़ियां चुराई थी। चार्जशीट के अनुसार शारिक का संबंध दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से है। वह नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल कर देश से भागा था। चार्जशीट में 79 आरोपियों के नाम शामिल है और सभी जेल में बंद हैं। पुलिस ने बताया कि अब इसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। चार्जशीट में समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी नाम शामिल है। वहीं स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल का भी नाम शामिल है।

मुझे हलके में मत लेना, जिसे जो समझना हो समझ ले

तमाम तरह की अटकलों के बीच एकनाथ शिंदे के बड़े बोल

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में चल रही अनबन की अटकलों के बीच डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दिया है। एकनाथ शिंदे ने दो टूक कहा है कि कोई भी उन्हें हलके में न ले और जिसे जो समझना है, वह समझ ले। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार बनने के बाद से ही शिंदे और फडणवीस में समय-समय पर टकराव की अटकलें लगती रही हैं। शिंदे कई बार अहम कार्यक्रमों को

छोड़कर अपने पैतृक गांव चले गए, जिसकी वजह से सवाल उठने लगे। वहीं, बीएमसी सरकार ने भी उनके 1400 करोड़ रुपये के टेंडर को खारिज करके शिंदे को झटका दिया था। इन सबके बीच, शिंदे ने नए बयान में कहा है कि उन्हें हलके में नहीं लिया जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा,मैंने पहले ही कहा है कि जिन्होंने मुझे हलके में लिया है... मैं एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन बाला साहेब ठाकरे और दिघे साहेब का कार्यकर्ता हूं और यह समझकर मुझे लेना चाहिए। जब हलके में लिया तो 2022 में पलट कर सरकार को बदल दिया और आम लोगों की सरकार लेकर आई। डबल इंजन की सरकार चली और उस समय कहा था कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे।

बिहार में गजब की शादी!

टीचर को पहले पीटा फिर छात्रा से कराया विवाह

भागलपुर (एजेंसी)। बिहार के भागलपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कहलगांव के सिंया गांव में एक बीपीएससी शिक्षक की जबरन शादी करा दी गई। बुधवार रात को ग्रामीणों ने शिक्षक की पिटाई की और एक छात्रा से मंदिर में शादी करवा दी। शिक्षक पर छात्रा से संबंध होने का आरोप था। छात्रा बीएससी की पढ़ाई कर रही है। शिक्षक बिहपुर के रहने वाले हैं और सिंया गांव में किराए पर रहते थे। वे छात्रा को ट्यूशन पढ़ाते थे। जानकारी के

अनुसार, बिहपुर निवासी गोपाल कुमार चौधरी गम्हरपुर मध्य विद्यालय में शिक्षक हैं। वे सिंया गांव में किराए के मकान में रहते थे। वह उसी गांव की एक छात्रा को उसके घर पर ट्यूशन पढ़ाते थे। छात्रा बीएससी की पढ़ाई कर रही है। बुधवार शाम को जब शिक्षक ट्यूशन पढ़ाने गए, तो ग्रामीणों और छात्रा के परिवार वालों ने उन्हें पकड़ लिया। ग्रामीणों और छात्रा के परिवार वालों ने शिक्षक पर छात्रा के साथ संबंध होने का आरोप लगाया। उन्होंने शिक्षक की जमकर पिटाई की और उनका मोबाइल भी तोड़ दिया। इसके बाद गांव के एक मंदिर में छात्रा की मांग में सिंदूर भरवाकर जबरन शादी करा दी। घटना की सूचना मिलते ही गुरुवार सुबह पुलिस सिंया गांव पहुंची और घटना की जानकारी ली।

सात दिन में लौटा दो लूटे हुए हथियार, इसके बाद खैर नहीं

मणिपुर के राज्यपाल ने दिया अल्टीमेटम, कहा-होगी सख्त कार्रवाई

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने लोगों को 7 दिनों के अंदर लूटे हुए हथियार वापस करने का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान भल्ला ने राज्य में पिछले 20 महीनों से जारी हिंसा और साम्प्रदायिक तनाव के मद्देनजर सभी समुदायों से शांति की अपील की है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से आग्रह किया है कि वे लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों और गोला-बारूद को निकटतम पुलिस स्टेशन, चौकी या सुरक्षा बलों के शिविर में अगले सात दिनों के भीतर स्वेच्छा से जमा कर दें। राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि एक सप्ताह के अंदर हथियार लौटाने पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बाद ऐसे हथियारों के कब्जे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के अपने पद से इस्तीफा देने के कुछ दिन बाद 13 फरवरी को हिंसा प्रभावित मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मणिपुर विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है, जिसका कार्यकाल 2027 तक है। मणिपुर में भाजपा सरकार का नेतृत्व कर रहे सिंह ने करीब 21 महीने की जातीय हिंसा के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

छग में नक्सलियों के बिछाए बारूदी सुरंग में विस्फोट

डीआरजी जवान घायल, एयरलिफ्ट कर पहुंचाया रायपुर

नारायणपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में बारूदी सुरंग की चपेट में आकर सुरक्षाबल का एक जवान घायल हो गया। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के छोटेडोंगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तोयमेटा और कवानार गांव के मध्य जंगल में बारूदी सुरंग की चपेट में आने से जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) का एक जवान घायल हो गया है।

पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार के दिन छोटेडोंगर थाने से जिला बल और डीआरजी के संयुक्त दल को गश्त के लिए रवाना किया गया था। अभियान के दौरान दोपहर लगभग 1.45 बजे तोयमेटा और कवानार के बीच जंगल में बारूदी सुरंग विस्फोट की चपेट में आने से डीआरजी का एक जवान घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद घायल जवान को जंगल से बाहर निकाला गया। फिलहाल जवान की हालत खतरे से बाहर है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक इलाज करने के बाद घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रायपुर भेजा जा रहा है।

मोदी सरकार की 'विकास नीति' बन गई रोल मॉडल

● मशहूर मैगजीन इकोनामिस्ट ने दी सलाह, भारत से सीखे यूरोप!

यूरोपीय देशों के 27 प्रतिनिधि जल्द करने वाले हैं भारत का दौरा

लंदन (एजेंसी)। भारत ने जब अमेरिका की नाराजगियों को दरकिनार करते हुए रूस से तेल खरीदा, पश्चिमी देशों की आपत्तियों के बावजूद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गले लगाया और जब यूक्रेन में रूसी हमले की निंदा भी नहीं की, तो यूरोपीय देशों की भौंहें तन गईं। पश्चिमी देशों की मीडिया में बात बात पर भारत की आलोचना की जाती रही है। पश्चिमी देशों के पत्रकारों ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। लेकिन अब इन्हीं यूरोपीय देशों के लिए भारत का विकास एक रोल मॉडल बन गया है। पश्चिमी देशों की जिस मीडिया ने लगातार भारत की आलोचना की, आज उनमें भारत के विकास मॉडल को लेकर कसीदें पढ़े जा रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट में लिखा गया है कि कैसे यूरोपीय देशों के लिए भारत एक रोल मॉडल बन गया है। यूरोपीय संघ के 27 कमीश्नरों की टीम इस महीने के अंत में भारत की एक यात्रा करने वाली है, जो उनके छोटे से प्रायद्वीप से बाहर एक दुर्लभ सामूहिक यात्रा होगी। मैगजीन ने लिखा है कि यूरोपीय देशों के अधीन रहा भारत भले ही कई खामियों से जूझ रहा हो, लेकिन यूरोपीय अधिकारियों को वहां बहुत कुछ दिखेगा, जिससे उन्हें ईर्ष्या होनी चाहिए। लेख में लिखा गया है कि उन बातों से वे सीख सकते हैं।

द इकोनामिस्ट की नजर में भारत क्यों है रोल मॉडल, मैगजीन ने यह भी बताया

मैगजीन ने लिखा है कि यूरोपीय अधिकारियों को सबसे बड़ी विशेषता जो देखने को मिलेगी, वो है आर्थिक विकास, जो उनके देशों के लिए पराया हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ समय से थोड़ी सुस्ती आई है और जीडीपी में साल-दर-साल मात्र 5.4 फीसदी की वृद्धि हुई है। फिर भी, यह यूरोपीय देशों के मुकाबले ये करीब 5.4 फीसदी ज्यादा है।

दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक अब कहलाएंगे आरोग्य मंदिर

● बीजेपी सरकार का बड़ा फैसला, 30 दिन में होगा बदलाव

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली की 553 मौजूदा मोहल्ला क्लीनिकों को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यू-एएएम) में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए 30 दिनों का लक्ष्य रखा गया है यानी 30 दिनों के भीतर दिल्ली के 553 मोहल्ला क्लानिक आरोग्य मंदिर में बदल जाएंगे। दिल्ली में सरकार बनने के बाद से मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदले जाने की खबरें थी। राजौरी गार्डन से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कहा था कि मोहल्ला क्लीनिकों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा जाएगा, ताकि वे लोगों की सेवा के वास्तविक केंद्र

बन सकें। बता दें, दिल्ली चुनाव के दौरान भाजपा ने मोहल्ला क्लीनिक के जरिए भी आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार और दिल्ली के लोगों को लूटने का आरोप लगाया था। ऐसे में भाजपा की सरकार आने के बाद मोहल्ला क्लीनिकों को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। ऐसे में दिल्ली सरकार ने मोहल्ला 30 दिनों के अंदर मोहल्ला क्लीनिक को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदलने का फैसला किया है। इससे पहले दिल्ली के नवगठित मंत्रिमंडल ने गुरुवार को अपनी पहली बैठक में राजधानी में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, महिला समृद्धि योजना पर चर्चा की और आठवीं विधानसभा के पहले सत्र में कैग की 14 लंबित रिपोर्ट पेश करने का भी निर्णय लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार ने शहर में स्वास्थ्य योजना लागू नहीं होने दी, जिससे लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाया था। उन्होंने कहा, ''पिछली सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को रोक दिया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे पूरे देश में लागू किया और अब हमने इसे दिल्ली के लिए मंजूरी दे दी है।'' मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को कुल 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा, जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार 5-5 लाख रुपये का योगदान देंगी।

यूपी सरकार विफल... इसको हटाया जाना चाहिए

मिशन 2027 में अभी से जुटने को कार्यकर्ताओं से राहुल ने किया आह्वान

कहा-यह सरकार नौकरियां देने में अक्षम है, सरकार से सवाल पूछने को कहा

रायबरेली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता एवं रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी की सरकार विफल सरकार है। इस सरकार को हटाया जाना चाहिए। केंद्र स्कूल, कॉलेजों का निजीकरण कर रही है। यह सरकार नौकरियां देने में सक्षम नहीं है। राहुल गांधी दो दिवसीय पर रायबरेली पहुंचे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया फेसबुक पर एक पोस्ट किया और लिखा, रायबरेली की मोहब्बत और

मिठास का कोई मुकाबला नहीं। दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को कांग्रेस नेता रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी ने युवा संवाद के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अभी जुट जाने के लिए कहा। अडाणी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मोदीजी अमेरिका जाकर कहते हैं कि मेरा पर्सनल मैटर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि दो हिन्दुस्तान है। एक अडाणी, अंबानी और एक गरीबों का हिन्दुस्तान है। राहुल गांधी ने लोगों से कहा कि आपने जो शादी देखी, वो उनका नहीं आपका पैसा है। दो हिन्दुस्तान नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए और आपको सवाल पूछना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार और बेरोजगारी पर सवाल पूछें।

महाशिवरात्रि पर काशी में भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था

45 घंटे तक खुला रहेगा मंदिर का गर्भगृह, झरोखा दर्शन की मिलेगी सुविधा

वाराणसी (एजेंसी)। काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 26 फरवरी को मंगला आरती के बाद गर्भगृह लगातार 45 घंटे खुला रहेगा। सुबह 2.30 बजे मंगला आरती के बाद मंदिर के कपाट खुलेंगे और 27 फरवरी की रात शयन आरती तक दर्शन का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान भक्त झरोखा दर्शन कर सकेंगे। मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। बुधवार को भगवान शिव के विवाह की रस्में पूरी की गईं। गुरुवार को उन्होंने बताया, 26 फरवरी को सुबह 2.30 बजे मंगला आरती के तुरंत बाद गर्भगृह के कपाट खोल दिए जाएंगे। उसके बाद, 27 फरवरी को शयन आरती तक कपाट खुले रहेंगे। प्रयागराज में चल रहे

महाकुंभ मेले के कारण काशी विश्वनाथ मंदिर में इन दिनों 5 से 7 लाख श्रद्धालु रोजाना आ रहे हैं। महाशिवरात्रि पर और भी भारी भीड़ की उम्मीद है। मंदिर प्रशासन भक्तों को सुगम दर्शन की सुविधा देने की पूरी तैयारी कर रहा है। कुंभ के बाद सात शैव अखाड़ों के नागा साधु भी अपनी पारंपरिक शोभायात्रा के साथ मंदिर पहुंचेंगे। सीईओ ने आगे बताया कि भक्तों को गर्भगृह के चारों द्वारों से झरोखा दर्शन की सुविधा मिलेगी। इस दौरान स्पर्श दर्शन की व्यवस्था नहीं रहेगी। झरोखा दर्शन का मतलब है कि भक्त

गर्भगृह के बाहर से ही शिवलिंग के दर्शन कर पाएंगे। 13 दिसंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद से, मंदिर में नए साल, महाशिवरात्रि और श्रावण के सोमवार जैसे अवसरों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। एक दिन में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के मामले में कई नए रिकॉर्ड बने हैं। महाकुंभ के दौरान तो एक दिन में आठ लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मेले की शुरुआत 13 जनवरी से अब तक दो करोड़ श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सीईओ ने बताया कि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में काशी विश्वनाथ धाम के सभी देवी-देवताओं का रुद्राभिषेक शुरू हो चुका है। यह एक पवित्र अनुष्ठान है जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसमें दूध, दही, घी, शहद, जल आदि से अभिषेक किया जाता है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर काशी विश्वनाथ के दर्शन का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए देश के कोने-कोने से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी आते हैं। मंदिर प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो।

डॉक्टरों की हड़ताल, दूसरे दिन भी प्रदर्शन

अमानक दवाइयों की जलाएंगे सांकेतिक होली, कहा-मरीजों की जान से हो रहा खिलवाड़

इंदौर (नप्र)। मध्यप्रदेश शासकीय-स्वशासी चिकित्सक महासंघ (एमटीए) ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया है। इसके दूसरे दिन, शुक्रवार को इंदौर के एमवाय अस्पताल के बाहर अमानक दवाइयों की सांकेतिक होली जलाई । एमटीए अध्यक्ष डॉ. राहुल रोकड़े के अनुसार, सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाइयों की सप्लाई से मरीजों और डॉक्टरों को परेशानी हो रही है। ये जीवन रक्षक दवाइयां हैं, लेकिन घटिया गुणवत्ता के कारण मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है। डॉक्टरों की मांग है कि ऐसी दवाइयों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगे और दोषी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने अमानक दवाइयां बनाने वालों को आजीवन कारावास की सजा देने की भी मांग की, ताकि भविष्य में मरीजों की जान से खिलवाड़ न हो।

बेअसर दवाइयां, डॉक्टरों की नाराजगी- डॉ. राहुल रोकड़े के मुताबिक, कई अमानक दवाइयां असरहीन हैं, जबकि इन्हें जीवन रक्षक माना जाता है। अगर ये दवाइयां काम नहीं करेंगी, तो डॉक्टरों को मरीज की हालत और मौत का सही कारण समझने में मुश्किल होगी। पहले भी कुछ दवाइयों को डॉक्टरों ने चिन्हित कर रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इन्हें अमानक घोषित किया था। डॉक्टरों का उद्देश्य जनता को इस गंभीर समस्या से अवगत कराना है। इसी कारण प्रदर्शन के दौरान इन अमानक दवाइयों की सूची मीडिया को भी दी जाएगी। उनकी मांग है कि मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति लागू हो, ताकि मरीजों को सुरक्षित और असरदार दवाइयां ही मिलें और डॉक्टरों को भी भरोसा रहे कि वे प्रभावी इलाज कर रहे हैं।

डॉक्टरों की अन्य मांगें

मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों ने निर्धारित समय सीमा के बाद भी हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया और न ही उच्च स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया गया। एसोसिएशन के अनुसार, पिछली उच्च स्तरीय समिति के निर्णयों के बावजूद मंत्री परिषद की बैठक में पारित विषयों पर 17 महीने बाद भी कैबिनेट के आदेश लागू नहीं किए गए। इसके अलावा, एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के खिलाफ हुई घटना की निंदा करते हुए डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है।

इंदौर को 8वीं बार सफाई में नंबर-वन बनाने की तैयारी

10 बिंदुओं पर होगा स्वच्छता का आकलन, पब्लिक पार्टिसिपेशन बनाता है शहर को खास

इंदौर (नप्र)। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर इंदौर तैयार है। 10 अलग-अलग बिंदुओं पर स्वच्छता का आकलन किया जाना है। स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम कभी भी इंदौर आ सकती है। टीम मौके पर जाकर अलग-अलग बिंदुओं को देखने के साथ ही लोगों से भी स्वच्छता को लेकर फीडबैक लेगी। इसके आधार पर फाइनल रैंकिंग मिलेगी। स्वच्छता में सात बार नंबर वन रह चुके इंदौर को आठवीं बार नंबर वन बनाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों सहित सफाई मित्र भी दिनरात मेहनत कर रहे हैं। अलग-अलग पैरामीटर पर इंदौर खरा उतरे इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी खुद फील्ड में जाकर कामों को चेक कर रहे हैं। कमी पेशी मिलने पर तुरंत उसे दुरुस्त भी किया जा रहा है।

यह हैं वह 10 पैरामीटर- स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के तहत नगर निकायों का आकलन विभिन्न मानकों के आधार पर किया जा रहा है। इसमें 10 हजार

अंकों का विस्तृत विभाजन किया गया है। इस सर्वेक्षण में 10 प्रमुख श्रेणियों के तहत नगर निकायों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें विजिबल क्लीननेस, सेग्रिगेशन कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एक्सेस ऑफ सेनिटेशन, यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, एडवोकेसी फॉर स्वच्छता. स्वच्छता कर्मियों का समग्र कल्याण, मशीनीकृत सेप्टिक टैंक सफाई सेवाएं, इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग एंड इंस्टीट्यूशन पैरामीटर, नागरिक प्रतिक्रिया और शिकायतों का निवारण शामिल हैं।

अब बात करते हैं इनके नंबर की- इन पैरामीटर में अंकों की बात करें तो सबसे ज्यादा अंक विजिबल क्लीननेस के 1500 अंक, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 1500 अंक और एडवोकेसी फॉर स्वच्छता के 1500 अंक है।

आईजी के ड्राइवर से धक्का-मुक्की

गाड़ी की चाबी निकालकर फेंकी ; बाइक सवारों पर केस दर्ज

इंदौर (नप्र)। इंदौर के राजेंद्र नगर में ग्रामीण आईजी के ड्राइवर के साथ तीन बाइक सवार युवकों ने गाड़ी निकालने की बात पर विवाद किया। उन्होंने कार की चाबी निकालकर धक्का-मुक्की की और अपशब्द कहे। ड्राइवर ने उनकी बाइक की फोटो खींचकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। राजेंद्र नगर पुलिस ने करण डागर निवासी एसएस सिटी सिलीकॉन की शिकायत पर बाइक सवार तीन युवकों के खिलाफ मारपीट और धमकाने का केस दर्ज किया हैं। करण ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 10 बजे वह अपनी कार से ड्यूटी जा रहे थे। पाटल्यापुरा के पास रास्ता संकरा होने के कारण उन्होंने बाइक सवारों से गाड़ी निकालने देने का अनुरोध किया, लेकिन वे बहस करने लगे। दो युवक बाइक से उतरकर बोले, 'पुलिस का रौब मत दिखाओ' और गाली-गलौज करते हुए कार की चाबी निकालकर दूर फेंक दी। करण ने तुरंत बाइक की फोटो ली और थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करण ग्रामीण आईजी अनुराग सिंह के यहां एमटी शाखा में पदस्थ हैं और ड्यूटी के लिए निकले थे। पुलिस ने घटना की जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

व्यापारी को पार्टनर संग कर रहे थे ब्लैकमेल; धमकाकर वसूले लाखों रुपए

इंदौर (नप्र)। जूनी इंदौर पुलिस ने हार्डवेयर व्यापारी की शिकायत पर हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक सुमित हार्डिया और उसके साथी सावन आसनानी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली का मामला दर्ज किया है। व्यापारी को लगातार धमकाने और वसूली के कारण उसने आत्महत्या का प्रयास भी किया था।

व्यापारी से पैसों की मांग और धमकियां

डीसीपी ऋषिकेश मीना के आदेश पर व्यापारी मुकेश हासेजा की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने व्यापारी से कहा कि अगर उसे अपने प्लॉट पर मकान बनाना है तो उन्हें पैसे देने होंगे। पैसे न देने पर काम रुकवाने और जान से मारने की धमकी दी गई। मुकेश हासेजा और उनके भाई किशोर हासेजा का माणिकबाग में एक संयुक्त प्लॉट है, जहां वे ठेकेदार विशाल गोगवानी से निर्माण करवा रहे थे। वहीं, सुमित और सावन का पास में कंसल्टेंसी ऑफिस है। आरोप है कि पिछले तीन महीने से दोनों आरोपी बिना किसी कानूनी आदेश के निर्माण कार्य रुकवा रहे थे।

ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली- मुकेश ने पुलिस को बताया कि 22 फरवरी 2024 को सुमित और सावन ने उन्हें अपने

ऑफिस बुलाकर कहा कि अगर मकान बनाना है तो उनकी बात माननी होगी। उन्होंने जबरन अपने ठेकेदार को काम में शामिल करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर दोनों भाइयों को धमकी दी और तीन लाख पचास हजार रुपए अलग-अलग किश्तों में वसूले। इतना ही नहीं, आरोपियों ने बिल्डिंग में बनने वाले पेंटहाउस को भी हड़पने की कोशिश की और जबरन कागजात उनके नाम करने को कहा। इसके लिए लगातार धमकियां दी गईं और मजदूरों को भगा दिया गया, जिससे तीन महीने से निर्माण कार्य बंद पड़ा है।

आत्महत्या के प्रयास और पुलिस कार्रवाई- लगातार मिल रही धमकियों के कारण किशोर हासेजा ने दो बार आत्महत्या का प्रयास किया। डर के कारण पीड़ितों ने प्लॉट पर जाना तक बंद कर दिया। राजनैतिक रसूख के चलते वे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से भी डर रहे थे। लेकिन बाद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत सौंपे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को नामजद किया और जल्द गिरफ्तारी की बात कही है।

पहले भी दर्ज हो चुके हैं मामले- सुमित हार्डिया के खिलाफ पहले भी स्काई लाइन रिसोर्ट के संचालक ने अवैध वसूली की शिकायत दर्ज कराई थी। उस मामले में भी सुमित ने धमकियां दी थीं और तोड़फोड़ की थी।

इंदौर में आईएमए का इंटरनेशनल कॉन्क्लेव शुरू

मैनेजमेंट पर देशभर के 26 दिग्गज करेंगे बात ; उद्योगपति, अर्थशास्त्री, नीति निर्माता होंगे स्पीकर्स

इंदौर (नप्र)। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन का 32वां अंतरराष्ट्रीय मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 21 फरवरी से ब्रिलिएंट कनवेंशन सेंटर में शुरू हुआ। सुबह साढ़े 9 से शाम 6 बजे तक चलने वाले इस दो दिनी आयोजन में 3 हजार से ज्यादा उद्योगपति, उद्यमी, अर्थशास्त्री, नीति निर्माता, स्टार्टअप संस्थापक और शिक्षाविद् हिस्सा लेंगे।ॉ इस बार कॉन्क्लेव की थीम उद्यमेन हि सिद्धयन्ति यानि संघर्ष, संकल्प और सफलता है। इस विषय के अंतर्गत व्यवसायिक परिदृश्य में बदलाव, वित्तीय क्षेत्र के नए आयाम, नेतृत्व के आधुनिक दृष्टिकोण और भारत की वैश्विक आकांक्षाओं पर चर्चा होगी। लाइफ टाइम अवॉर्ड गोदरेज इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष नादिर बुरोरजी गोदरेज को मिलेगा।

पहले दिन इन्हें सुनने का मौका- 21 फरवरी को पहले दिन जीवन कोच और प्रमुख वक्ता पूज्य ज्ञान वत्सल स्वामी, आध्यात्मिक गुरु डॉ. स्वामी महेश योगी, आईआईएम इंदौर के निदेशक हिमांशु राय, गो मैकनिक डॉट इन की सह-संस्थापक मुस्कान कक्कड़, स्टैक बॉक्स के सह-संस्थापक नितिन मामोडिया, होम लेन के सह-संस्थापक श्रीकांत अय्यर, न्यू ब्रॉडकास्ट बिजनेस के वरुण कोहली आदि का संबोधन होगा।

किसानों के हित में संभागायुक्त सख्त

अमानक खाद-बीज बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, डीडीए को नोटिस

इंदौर (नप्र)। इंदौर संभागायुक्त कार्यालय में कृषि विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें संभागायुक्त दीपक सिंह ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। संभागायुक्त ने जोर दिया कि कृषि विभाग के नवाचारों की जानकारी किसानों तक पहुंचे। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बैठक में अमानक खाद, बीज और उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। संभागायुक्त ने स्पष्ट किया कि केवल लाइसेंस निलंबित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसानों को हुए नुकसान का आकलन भी किया जाए। उन्होंने जिला उप संचालकों को फील्ड में जाकर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। दीपक सिंह ने कहा कि अमानक सामग्री से किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ उनका पूरा सीजन भी प्रभावित होता है। उन्होंने सभी डीडीए को निर्देश दिया कि इंस्पेक्टरों के माध्यम से अमानक सामग्री के नमूने एकत्र कर उनकी जांच में सख्ती बरती जाए। बैठक में इंदौर, धार, बड़वानी, आलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर जिलों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। खराब प्रदर्शन के चलते खरगोन जिले के डीडीए को शोकॉज नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए।

जीआईएस के लिए इंदौर एयरपोर्ट स्टैंडबाय पर

भोपाल में जगह कम पड़ने पर इंदौर में पार्क कराएंगे वीवीआईपी के प्राइवेट जेट-चार्टर

इंदौर (नप्र)। 24 और 25 जनवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट को लेकर इंदौर में भी तैयारियां की जा रही है। इस समिट में देश-दुनिया से कई वीआईपी शामिल होंगे। कई वीवीआईपी अपने विशेष विमानों से इस समिट में शामिल होने के लिए आने वाले हैं। इसे देखते हुए भोपाल के साथ ही इंदौर एयरपोर्ट पर भी तैयारियां की जा रही है। बताया जा रहा है कि जब भोपाल एयरपोर्ट पर जगह की कमी आएगी तब विमानों को इंदौर एयरपोर्ट पर पार्क करने के लिए भेजा जाएगा। इंदौर एयरपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक भोपाल एयरपोर्ट 24 घंटे खुला रहने वाला एयरपोर्ट है। भोपाल में विमानों की पर्याप्त पार्किंग उपलब्ध है। इसके बाद भी सरकार ने मेहमानों को बेहतर सेवा

देने के लिए इंदौर एयरपोर्ट को किसी भी स्थिति के लिए स्टैंडबाइ पर रखा है।

यानी अगर कभी भी जरूरत पड़ती है, तो भोपाल आने वाले मेहमानों के विमानों को इंदौर में उतारा और पार्क किया जा सकेगा। इंदौर एयरपोर्ट पर 26 विमानों की पार्किंग उपलब्ध है। भोपाल में अगर नियमित उड़ानों के अतिरिक्त ज्यादा विमान आने पर पार्किंग की कमी पड़ती है, तो मेहमानों को वहां उतारने के बाद विमानों को इंदौर में पार्क करने की व्यवस्था की गई है।

बिना अनुमति नहीं बनेंगे डिवाइडर, स्पीड ब्रेकर

चालानी कार्रवाई के साथ बसों की जब्ती भी होगी, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हुए कई निर्णय

इंदौर (नप्र)। शहर में बेवजह इधर-उधर खड़ी होने वाली यात्री बसों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ बसों की जब्ती भी होगी। इसके लिए जिला प्रशासन, यातायात पुलिस, नगर निगम और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त मुहिम चलाई जाएगी। अब शहर में कहीं भी बगैर अनुमति के डिवाइडर और स्पीड ब्रेकर नहीं बनेंगे। इसके लिए सड़क सुरक्षा समिति से अनुमति लेना होगी। यह निर्णय गुरुवार को कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि शहर में बड़ी संख्या में यात्री बसें इधर-उधर खड़ी रहती हैं । इस पर सख्ती से कार्रवाई की आवश्यकता है। ऐसी बसें जो सरवटे और गंगवाल बस स्टैंड से चलती हैं, उनकी पार्किंग के लिए समुचित स्थान का चयन किया जाएगा। बैठक में देवास नाका पर बन रहे फ्लाईओवर के मद्देनजर ट्रैफिक प्लान पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिया

गया। इस दौरान सुझाव दिया गया कि यहां यातायात को सुगम बनाने के लिए फ्लाईओवर की डिजाइन में परिवर्तन कर लम्बाई बढ़ाई जाए। नेशनल हाईवे 52, एमआर-10 जंक्शन पर बन रहे फ्लाईओवर के मद्देनजर ट्रैफिक डायवर्सन प्लान को भी मंजूरी दी गई। कलेक्टर ने कहा कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे यातायात भी सुगम बना रहे और फ्लाईओवर का निर्माण भी तेजी से चलता रहे। इंडस्ट्री हाउस, गीता भवन चौराहा और जीपीओ चौराहे के लेफ्ट टर्न को भी व्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए गए।बैठक में राजीव गांधी और चोइथराम चौराहे पर सुव्यवस्थित यातायात में बाधक अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश भी दिए गए।

इंदौर के धरावराधाम में शिव पुराण कथा आज से

कर्नाटक के राज्यपाल गेहलोत करेंगे उद्घाटन, एक हजार परिवारों को मिलेगी रामायण

इंदौर (नप्र)। इंदौर के धार रोड स्थित धरावराधाम में एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। ब्रह्मलीन महंत

घनश्यामदास महाराज की 16वीं स्मृति में अखिल भारतीय मानस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 22 फरवरी से शुरू होगा। प्रख्यात मनीषी पंडित पुष्पानंदन पवन तिवारी शिव पुराण कथा का वाचन करेंगे। महंत शुकदेवदास महाराज के सान्निध्य में कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गेहलोत मुख्य अतिथि होंगे। सांसद शंकर लालवानी, समाजसेवी गोपाल गोयल और भाजपा नेता गोपाल चौधरी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम संयोजक डॉ. सुरेश चोपड़ा और ललित अग्रवाल ने बताया कि राज्यपाल व्यासपीठ और शिव पुराण की पूजा-अर्चना करेंगे। इस अवसर पर आसपास के 25 गांवों से आए श्रद्धालुओं को रामायण ग्रंथ भेंट किया जाएगा। यह एक हजार परिवारों को रामायण से जोड़ने के प्रकल्प की शुरुआत होगी।

शिव पुराण कथा प्रतिदिन दोपहर 1 से 5 बजे तक होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धरावराधाम में शामियाना लगाया गया है। मानस सम्मेलन में देश-प्रदेश के कई प्रमुख मानस मर्मज्ञ और संत-विद्वान शामिल होंगे।

कोमा में डॉक्टर, पिता ने 75 लाख क्लेम मांगा

इंदौर कोर्ट ने माना कभी ठीक नहीं होंगे, राशि बढ़ाकर 81 लाख देने का कहा

इंदौर (नप्र)। इंदौर में कोर्ट ने एक इंश्योरेंस कंपनी को डॉक्टर के परिवार को 81.95 लाख रुपए देने का आदेश दिया। इंश्योरेंस कंपनी को यह राशि दो साल के ब्याज सहित कुल 95 लाख रुपए चुकानी होगी। दरअसल, बड़वानी जिले के रहने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर हरीश गोले (45) का 4 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद से वे कोमा में हैं। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि उनके होश में आने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन डॉ. हरीश के माता-पिता को अभी भी आस है कि उनके बेटे को एक दिन होश आएगा। डॉ. हरीश के परिवार ने इलाज के लिए कोर्ट में 75.50 लाख रुपए के क्लेम का केस दायर किया था। मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर के बयान के आधार पर कोर्ट ने माना कि हरीश 100 प्रतिशत कोमा में हैं और ताउम्र इसी स्थिति में रहेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने क्लेम राशि में 5 लाख रुपए की बढ़ोतरी करते हुए 81.95 लाख रुपए देने के आदेश दिए। ब्याज समेत ये राशि 95 लाख रुपए है। प्रदेश में संभवत यह पहला मामला है, जब कोर्ट ने पीड़ित पक्ष द्वारा मांगी गई राशि से 5 लाख रुपए अधिक का मुआवजा मंजूर किया है।

डॉ. हरीश गोले

तेज रफ्तार बाइक ने मारी थी टक्कर- डॉ. हरीश गोले का बड़वानी जिले के मेनीमाता में खुद का होम्योपैथिक क्लिनिक था। 2 मार्च 2021 को वे बाइक से बलवाड़ी से धवली रोड स्थित अपने क्लिनिक जा रहे थे। तभी एक बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में डॉ. गोले के सिर, चेहरे और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। उनका प्राथमिक इलाज वरला (सेंधवा) के प्राथमिक अस्पताल में किया गया। फिर गणेश मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, धुलिया रेफर किया गया।

इंदौर में तीन हॉस्पिटल में चला इलाज- अस्पताल में हालत में कोई सुधार न होने पर सीएचसी हॉस्पिटल, इंदौर भेजा गया, जहां डेढ़ माह तक उनका इलाज चला। इस दौरान सिर और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई। इसके बाद उन्हें आनंद हॉस्पिटल में 15 दिन तक रखा। फिर डीएनएस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, लेकिन यहां एक दिन बाद ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।

सिर में गहरी चोट से कोमा में गए- सिर में गहरी आंतरिक चोट लगने के कारण डॉ. गोले पूरी तरह होश में नहीं आ सके। घर में ही पिछले चार साल से वे बिस्तर पर हैं। उन्हें ट्यूब के माध्यम से जूस, दूध और दवाइयां दी जा रही हैं। माता-पिता उनकी दिन-रात देखभाल कर रहे हैं।

एक साल बाद पिता ने लगाया क्लेम केस- डॉ. हरीश के बुजुर्ग पिता सोहनलाल गोले पेशे से किसान हैं। मां बीना घर संभालती हैं। बेटे की गंभीर स्थिति और इलाज में हुए भारी खर्च को देखते हुए, उन्होंने 7 जनवरी 2022 को अपने वकील अरुण त्रिपाठी के माध्यम से जिला कोर्ट, इंदौर में क्लेम केस दायर किया। यह मामला बाइक सवार दिनेश पिता धरमसिंह तरोले (निवासी वरला), बाइक मालिक संदेश तरोले और दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ दर्ज किया गया। याचिका में बेटे के इलाज में हुए खर्च और परिवार की आजीविका को ध्यान में रखते हुए 75 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की गई।

कोर्ट में तीन बार स्ट्रेचर पर लाए गए डॉ. हरीश- दो साल तक चली सुनवाई के दौरान तीन बार डॉ. हरीश को कोमा की हालत में चलित स्ट्रेचर पर कोर्ट लाया गया। यहां कोर्ट की टीम ने उनका प्रत्यक्ष परीक्षण किया और उनकी मौजूदा स्थिति का आकलन किया। दरअसल, इस तरह के मामलों में कोर्ट के समक्ष पीड़ित की वास्तविक स्थिति को देखना जरूरी होता है। डॉ. हरीश 4 साल से कोमा में हैं, इसलिए उन्हें एक सुरक्षित वाहन में कोर्ट परिसर तक लाया गया, जहां बाहर ही उनका परीक्षण किया गया।

संपादकीय

ट्रंप के 'खुलासे' में सच्चाई कितनी?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले माह में अब तक यही साबित किया है कि वो बतौर राष्ट्रपति दूसरी पारी में पहले की तुलना में ज्यादा अगंभीर और अविश्वसनीय हैं। वो कब क्या कहेंगे और क्या करेंगे, कब पलटी मार जाएंगे, कब किस पर कुछ भी आरोप जड़ देंगे। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसी श्रृंखला में ट्रंप ने ताजा आरोप अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जो बाइडेन को घेरने के लिए जड़ा है, उसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। भारत में इसको लेकर विपक्षी कांग्रेस और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच तलवारें खिंच गई हैं। अगर यह आरोप सही है तो बेहद गंभीर है। हाल में ट्रंप अमेरिका द्वारा यूएसएड के तहत 182 करोड़ रु. की सहायता रोके जाने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा था कि इस राशि से पूर्व राष्ट्रपति भारत के आम चुनाव में मोदी के बजाए किसी और को चुनाव जिताना चाहते थे। ट्रंप ने यह 'खुलासा' गुरुवार को अमेरिकी शहर मियामी में सऊदी सरकार की फ्यूचर इंवेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में किया। उन्होंने कहा कि मेरे राष्ट्रपति बनने से पहले सरकारी खजाने का मनमाने तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। हम इस बारे में भारत सरकार को बताएंगे। गौरतलब है कि यह राशि यूएसएड के दिए जाने वाले 4 हजार करोड़ रू. के अंतरराष्ट्रीय फंड का हिस्सा है। भारत तक यह पैसा कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग (सीईपीपीएस) नाम की संस्था को दिया गया था। इस संस्था के तीन NGO, IFES (चुनाव जागरूकता के लिए), NDI (लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए) व IRI (नागरिक भागीदारी बढ़ाने के लिए) हैं। सीईपीपीएस ने यह पैसा एशिया में काम करने वाले एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शन नाम के एनजीओ को दिया। वहां से भारत में आईएफईएस को मिला। बताया जाता है कि इस पैसे का इस्तेमाल मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया। ट्रंप के इस आरोप से सीधे-सीधे विपक्षी कांग्रेस संदेह के घेरे में आ गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्रंप के दावों को बेतुका बताते हुए मोदी सरकार से यूएसएड पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि ट्रंप की बातों को सीरियसली नहीं लिया जा सकता क्योंकि अमेरिकी मदद का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। वहीं भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने कहा, पीएम मोदी अपनी चुनावी सभाओं में विदेशी दखल के बारे में चेता चुके हैं। मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन ताकतों के मोहरा हैं। वे अमेरिका-ब्रिटेन में भारत विरोधी दुष्प्रचार में शामिल रहे। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्रंप के खुलासे से साफ हो गया है कि अब तक अमेरिका से जो फंडिंग हो रही थी, उसका इस्तेमाल भारत में चुनाव को प्रभावित करने, नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने की साजिश में किया जा रहा था। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस जब सीधे चुनाव में मोदी को नहीं हरा पा रही है, तो जॉर्ज सोरोस जैसे भारत विरोधियों से मदद ले रही है। ट्रंप के खुलासे की तह में जाना जरूरी है। क्योंकि यह केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है। अगर अमेरिका ने भारत में चुनावों को प्रभावित करने के लिए फंडिंग की है तो यह अत्यंत गंभीर और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अमेरिका की अनावश्यक और अवांछनीय दखलंदाजी है। यह साफ होना भी जरूरी है कि भारत में जिस एनजीओ को यह पैसा पहुंचाया गया वो किसका है और उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता क्या है। अगर ट्रंप केवल भारत को यूएसएड बंद करने को जायज ठहराने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो यह हास्यास्पद ही है।

चार दशक का 'गंगा मुक्ति आंदोलन'

नजरिया

कुमार कृष्णन

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

22 फरवरी को कहलगांव में 43 साल पहले, 1982 में शुरु हुए 'गंगा मुक्ति आंदोलन' की चवालीसवीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। गंगा बेसिन के इलाकों के महत्वपूर्ण सवाल को लेकर दो दिनों तक कागजी टोला, कहलगांव, भागलपुर में पुनः देश भर के परिवर्तनवादी जुटेंगे और आगे की योजना बनाएंगे। इस लिहाज से आंदोलन का शंखनाद दो दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। एक तो शासन तंत्र पर दबाव बनाने लिए, दूसरे सांगठनिक मजबूती के लिए। इस जमावड़े के मौके पर लगभग चार दशकों के 'गंगा मुक्ति आंदोलन' के प्रभावों और बरकरार रहने पर बातचीत करना प्रासंगिक होगा।

गंगा की जमींदारी के खिलाफ शुरू हुआ यह आन्दोलन 1987-88 आते-आते बिहार के सम्पूर्ण गंगा क्षेत्र में फैल गया था और इसमें लाखों लोग शामिल हो गए थे। जब कुर्सेला से पटना तक (लगभग 500 किलोमीटर) नौका जुलूस निकाला गया तो गंगा-तट के गांव-गांव में स्त्री-पुरुषों की भागीदारी और उनका उत्साह देखने लायक था। इस नौका जुलूस के बाद जब बिहार के सम्पूर्ण गंगा क्षेत्र में 'जलकर' (मछली पकड़ने के एवज में दिया जाने वाला टैक्स) बंद कर दिया गया तो पानी के ठेकेदारों ने अनेक प्रकार के जुल्म ढाए। अन्ततः 1990 की जनवरी में सरकार को बाध्य होकर गंगा समेत बिहार की सभी नदियों की बहती धारा में परम्परागत मछुआरों के लिए मछली पकड़ना कर-मुक्त कर दिया गया।

1993 के पहले गंगा में जमींदारों की पानीदारी थी, जो गंगा के मालिक बने हुए थे। सुल्तानगंज से लेकर पीरपैंती तक 80 किलोमीटर के क्षेत्र में 'जलकर जमींदारी' थी। यह जमींदारी मुगलकाल से चली आ रही थी। सुल्तानगंज से बरारी के बीच की जमींदारी महाराज घोष की थी। बरारी से लेकी, पीरपैंती तक मकससपुर की आधी-आधी जमींदारी क्रमशः मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के मुसर्रफ हुसैन प्रमाणिक और महाराज घोष की थी। हैरत की बात थी कि जमींदारी किसी आदमी के नाम पर नहीं, बल्कि देवी-देवताओं के नाम पर थी। ये देवता थे - श्री श्री भैरवनाथ जी, श्री श्री ठाकुर वासुदेव राय, श्री शिवजी एवं अन्य। कागजी तौर जमींदार की हैसियत केवल सेवायत की रही है।

वर्ष 1908 के आसपास बाढ़ प्रभावित दियारे की जमीन का काफी उलट-फेर हुआ था। जमींदारों ने जमीन पर कब्जा किया था। नतीजे में किसानों में आक्रोश फैला था। संघर्ष की चेतना पूरे इलाके में फैली; 'जलकर जमींदार' इस जन-जागृति से भयभीत हो गये और 1930 के आसपास ट्रस्ट बनाकर इसे देवी-देवताओं के नाम कर दिया। 'जलकर जमींदारी' खत्म करने के लिए 1961 में एक कोशिश की गयी; भागलपुर के तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर ने इसे खत्म कर मछली बंदोबस्ती की जवाबदेही सरकार पर डाल दी। मई 1961 में जमींदारों ने उच्च न्यायालय में इस कार्रवाई के खिलाफ अपील की और अगस्त 1961 में जमींदारों को स्टे-ऑर्डर मिल गया।

1964 में उच्च न्यायालय ने जमींदारों के पक्ष में फैसला सुनाया तथा तर्क दिया कि 'जलकर' की जमींदारी यानी 'फिशरीज राइट' मुगल बादशाह ने दिए थे। अदालत ने कहा कि 'जलकर' के अधिकार का प्रश्न जमीन से अलग है, क्योंकि जमीन की तरह यह अचल संपत्ति नहीं है। इस कारण यह 'बिहार भूमि-सुधार कानून' के अंतर्गत नहीं आता। बिहार सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की और सिर्फ एक व्यक्ति मुसर्रफ हुसैन प्रमाणिक को पार्टी बनाया।

'गंगा मुक्ति आंदोलन' के अनिल प्रकाश के अनुसार आरंभ में जमींदारों ने इसे मजाक समझा और आंदोलन को कुचलने के लिए कई हथकंडे अपनाये, लेकिन आंदोलनकारी अपने संकल्प- 'हमला चाहे कैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा'- पर अडिग रहे और निरंतर आगे बढ़े। संघर्ष के नतीजे में 1988 में बिहार विधानसभा में मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए जल-संसाधनों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का एक प्रस्ताव लाया गया। कहलगांव के पत्रकार प्रदीप विद्रोही के अनुसार, मछुआरा समाज की इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका रही है और आज भी बनी हुई है। इसके साथ ही किसानों,मजदूरों, झुग्गीवासियों, बुनकरों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों, कवियों, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भागीदारी ने इस आंदोलन को सशक्त और व्यापक बनाया था।

आंदोलन से जुड़े उदय बताते हैं कि 'जातिप्रथा के जहर के खिलाफ चेतना जाग्रत करना हमारे आंदोलन का अभिन्न हिस्सा रहा है। 1982 में आयोजित 'एकलव्य मेला' से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1984 में इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या के खिलाफ जब सिख विरोधी उत्पात शुरू हुआ तो साथियों ने आगे बढ़कर उसे रोका। भागलपुर और पटना में साम्प्रदायिक दंगे और तनाव हुए तो आंदोलन के लोगों ने जान पर खेलकर उसे रोकने की कोशिश की। यह सब 'गंगा मुक्ति आंदोलन' की व्यापक वैचारिक दृष्टि के कारण ही सम्भव हो सका।'

अनिल प्रकाश के अनुसार - जब 'गंगा मुक्ति आंदोलन' ने फरक्का-बराज को विनाशकारी बताया तो बहुतों ने खिल्ली उड़ाई थी। जब 'कहलगांव सुपर थर्मल-पावर स्टेशन' का आंदोलन ने विरोध किया तो हमें विकास विरोधी बताया गया। जब हम सबने रासायनिक खादों और जहरीले रासायनिक कीटनाशकों पर रोक लगाने की मांग की तब भी हमारा मजाक उड़ाया गया। सुन्दरलाल बहुगुणा और उनके साथी टिहरी बांध के निर्माण का विरोध कर रहे थे तो 'गंगा मुक्ति आंदोलन' भी उनके साथ था।

आज साबित हो रहा है कि हम सही रास्ते पर थे और दूसरों से आगे देख रहे थे। आज नदियां और ज्यादा जहरीली हो गई हैं, हमारे खेत जहरीले हो रहे हैं, उसमें उगने वाले अनाज, फल और सब्जियां जहरीली हो रही हैं, हमारी मछलियां भी जहरीली होती जा रही हैं। यहां तक कि सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा भी शहरों में नहीं मिलती। आंदोलन 1980 के दशक की शुरुआत से ही इसे चीखकर कह रहा था। मनुष्य और प्रकृति के मधुर सम्बन्धों की बुनियाद पर समता मूलक लोकतांत्रिक समाज बनना हमारा लक्ष्य है। हम सब इस दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आंदोलन के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर केएस बिलग्रामी ने ठीक ही कहा था कि 'इकोलॉजी और इकॉनोमिक्स' के बीच संतुलन बिठाकर चलना पड़ेगा।

फरक्का-बराज के कारण हमारी मछलियां समाप्तप्राय- हैं जिससे लाखों लोगों की रोजी-रोटी छिन गई और सामान्य जन के लिए सुलभ पौष्टिक भोजन की कमी हो गई है। मछुआरों का कहना है कि पहले गंगा में तमाम किस्म की मछलियां मिलती थीं, जैसे-हिलसा, झींगा, पंगास, सौकची, कुर्सा, कठिया, गुल्ला, महसीर, कतला, रेहू, सिंघा आदि जो अब मुश्किल से ही दिखती हैं। हिलसा तो फरक्का के ऊपर लगभग लुप्त हो गई है। यह मछली प्रजनन के लिए समुद्र से नदी के मीठे पानी में जाती है। फरक्का-बराज ने हिलसा का रास्ता रोक दिया है। फरक्का-बराज के कारण गंगा अब ज्यादा रफ्तार से रास्ता बदल रही है, जिससे कटाव बढ़ा है। जब नदी उथली होती है तो फैलने लगती है और अपने किनारों पर दबाव डालती है।

मछलियों के लुप्त होने के लिए यहां के निवासी फरक्का-बराज के अलावा नदी किनारे बने ईंट-भट्टे, रेत खनन, प्रदूषण, गलत तरीके से मछली पकड़ने और विदेशी मछलियों को भी जिम्मेदार मानते हैं। गंगा और इसकी सहायक नदियों में मिट्टी-बालू भर गई है और बाढ़ तथा जल-जमाव की समस्या बढ़ती चली जा रही है। जलकर जमींदारी के खत्म होने के बाद भागलपुर में गंगा नदी में सुल्तानगंज के जहांगीरा (घोरघट पुल) से पीरपैंती के हजरत पीरशाह कमाल दरगाह तक, बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग ने 11 दिसंबर 1991 को पारंपरिक मछुआरों के लिए निःशुल्क घोषित किया है।

फरक्का के अलावा भागलपुर जिले के कहलगांव स्थित 'नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन' (एनटीपीसी) का सवाल गंभीर है। 'एनटीपीसी' के इस कोल पावर प्लांट का निर्माण 1985 में शुरू हुआ था और इससे विद्युत उत्पादन 1992 में शुरू हुआ। शुरुआत से ही 'गंगा मुक्ति आंदोलन' और स्थानीय पर्यावरणविदों ने इसके निर्माण पर आपत्ति जताई थी। गंगा नदी के किनारे बसा यह इलाका खेती के लिहाज के काफी उर्वर है। प्रदूषण के कारण यहां पेड़ों की हरियाली समाप्त हो गई है। पेड़ के पत्तों पर राख की मोटी परतें बिछी हुई हैं। और तो और प्रदूषण के कारण लोगों में सांस फूलने की समस्या और विकलांगता बढ़ी है। यह धान, आम और पान का इलाका रहा है, मगर 'एनटीपीसी' की वजह से सब नष्ट हो गया। (सप्रेस)

विवाह के झूठे वादों से दुष्कर्म के बढ़ते मामले

सरोकार

प्रियंका सौरभ

लेखक स्तंभकार हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल झूठी शादी की शपथ की आड़ में कई हज़ार बलात्कार के मामले दर्ज किए जाते है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अतुल गौतम मामले में 2025 में दिए गए फैसले से यह सवाल उठता है कि न्यायिक व्याख्याएँ महिलाओं की स्वायत्तता और कानूनी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती हैं। बलात्कार और सेक्स के लिए सहमति देना स्पष्ट रूप से अलग-अलग हैं। इन स्थितियों में, न्यायालय को सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या शिकायतकर्ता की पीड़िता से शादी करने की वास्तविक इच्छा थी या उसके कोई छिपे हुए उद्देश्य थे और उसने केवल अपनी वासना को शांत करने के लिए इस आशय का झूठा वादा किया था, क्योंकि बाद वाले को धोखा या छल माना जाता है। इसके अतिरिक्त, झूठा वादा न निभाने और उसे तोड़ देने में अंतर है। अभियुक्त द्वारा अभियोक्ता को यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए लुभाने के इरादे के बिना किया गया वादा बलात्कार के रूप में मान्य नहीं होगा। अभियोक्ता अभियुक्त द्वारा बनाए गए झूठे प्रभाव के बजाय उसके प्रति अपने प्यार और जुनून के आधार पर अभियुक्त के साथ यौन सम्बंधों के लिए सहमति दे सकती है।

वैकल्पिक रूप से, अप्रत्याशित या अनियंत्रित परिस्थितियों के कारण ऐसा करने का इरादा होने के बावजूद अभियुक्त उससे शादी करने में असमर्थ हो सकता है। इन स्थितियों को अलग तरीके से संभालने की आवश्यकता है। बलात्कार का मामला तभी स्पष्ट होता है जब शिकायतकर्ता का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा या गुप्त उद्देश्य हो। अतुल गौतम बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फ़ैसला सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है। यह फ़ैसला अपर्णा भट बनाम के विपरीत है। 2021 के मध्य प्रदेश राज्य के फैसले में आरोपी और पीड़ित को द्वितीयक आघात से बचने के लिए जमानत पर रहते हुए संवाद करने से मना किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला सुनाया कि निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी के लिए, जमानत की आवश्यकताओं को आरोपी और उत्तरजीवी के बीच संचार के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। यह विचार कि विवाह बलात्कार के लिए एक उपाय है न कि अपराध के लिए सजा, ऐसी जमानत आवश्यकताओं द्वारा पुष्ट होता है, जो सामाजिक समझौते को कानून के शासन से आगे रखता है। रामा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) में जमानत देते समय इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसने प्रतिवादी के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर दिया। उत्तरजीवी को जमानत प्राप्त करने के लिए आरोपी द्वारा विवाह के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कानूनी व्यवस्था के भीतर निरंतर दुर्व्यवहार हो सकता है। अभिषेक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024) ने न्याय की गारंटी देने के बजाय, अभियुक्त को विवाह के वादे के बदले में जमानत देकर एक दबावपूर्ण गतिशीलता बनाई। जो उत्तरजीवी को उचित पुनर्वास सहायता प्राप्त करने के बजाय अभियुक्त पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करता है। किशोरों के निजता के अधिकार (2024) में न्यायालय द्वारा उत्तरजीवियों और बच्चों को आवास, शिक्षा और परामर्श प्रदान करने के राज्य के दायित्व पर प्रकाश डाला गया था। जमानत का उद्देश्य सामाजिक कर्तव्यों को लागू करना नहीं है, बल्कि मामला लंबित रहने तक अस्थायी स्वतंत्रता की गारंटी देना है।

महिलाओं की स्वायत्तता और 'सम्मान' विचारधारा की निरंतरता इन न्यायिक निर्णयों से प्रभावित होती है, जो लैंगिक रूढ़ियों को भी मज़बूत करती है। ऐसे निर्णय बलात्कार को अपराध से कम और पवित्रता के नुक़सान को अधिक बनाते हैं, जो पितृसत्तात्मक धारणा को मज़बूत करते हैं कि एक महिला की गरिमा विवाह से जुड़ी होती है। न्यायालयों ने पिछले कई निर्णयों में एक पीड़ित के पुनर्वास को विवाह के बराबर माना है, बलात्कार को शारीरिक स्वायत्तता के उल्लंघन के रूप में स्वीकार करने में विफल रहे। न्यायालय महिलाओं की स्वायत्तता को कमजोर करते हुए अपराधियों के साथ विवाह करने के लिए पीड़ितों पर दबाव डालकर कानूनी संरक्षण के तहत दुर्व्यवहार और नियंत्रण को बढ़ावा देते हैं। विवाह को एक उपाय मानने वाली अदालतें पीड़ित की सहमति की कमी को नजरअंदाज करती हैं, जिसका अर्थ है कि जबरदस्ती को कानूनी रूप से उचित ठहराया जा सकता है। महिलाओं को लगातार आघात और सुरक्षा जोखिमों के बावजूद अक्सर अपने दुर्व्यवहार करने वालों के साथ 'समझौता विवाह' में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हुए, जो महिलाओं की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा करता है, ऐसे निर्णय महिलाओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध सम्बंधों में मजबूर करके उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, जबरन विवाह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं, जिससे पीड़ितों को न्याय के बजाय अधिक शोषण का सामना करना पड़ता है।

ये निर्णय इस धारणा को बनाए रखते हैं कि विवाह यौन हिंसा को हल कर सकता है, इन घटनाओं को गंभीर अपराधों के बजाय नागरिक विवादों में बदल देता है। रूढ़िवादी ग्रामीण क्षेत्रों में पीड़ितों पर अक्सर अदालतों द्वारा आरोपी लोगों से विवाह करने का दबाव होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक दबाव से न्याय से समझौता न हो, अदालतों को स्थापित नियमों का पालन करना चाहिए जो विवाह को जमानत की शर्त बनाने से रोकते हैं। अपर्णा भट केस (2021) में, सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला किया कि जमानत की ऐसी आवश्यकताएँ जो पीड़ितों को रिश्तों में मजबूर करती हैं या लैंगिक रूढ़िवादिता को बनाए रखती हैं, उनसे बचना चाहिए। राज्य को पीड़ितों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए मौद्रिक सहायता, परामर्श, कानूनी सहायता और कौशल-निर्माण पाठ्यक्रम प्रदान करके कल्याण कार्यक्रमों में सुधार करना चाहिए। वन स्टॉप सेंटर योजना द्वारा एकीकृत सहायता सेवाएँ प्रदान की जाती हैं; हालाँकि, अधिकतम प्रभाव के लिए, इसमें सुधार और विस्तार की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक विवेक से पीड़ितों के अधिकारों को ख़तरा न हो, विधायी संशोधनों को विशेष रूप से विवाह की शर्त पर ज़मानत देने की प्रथा को रोकना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानूनी व्याख्याएँ पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों के बजाय संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखें, न्यायाधीशों को लिंग-संवेदनशील प्रशिक्षण प्रदान करें। पीड़ितों के अधिकारों और लैंगिक न्याय को न्यायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा संचालित पाठ्यक्रम।

त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए, त्वरित परीक्षण पीड़ितों को समझौते के लिए मजबूर करने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई की आवश्यकता को समाप्त कर देंगे। हालाँकि 2019 निर्भया फंड को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए अलग रखा गया था, लेकिन उनमें से कई अभी भी संसाधनों की कमी और प्रशासनिक रुकावटों के परिणामस्वरूप कम उपयोग किए जाते हैं। ऐसे न्यायिक निर्णयों से महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करने और इस तरह पितृसत्तात्मक मानदंडों को मज़बूत करने का जोखिम है। रिश्ते की जटिलता और धोखाधड़ी के इरादे के बीच अंतर करने के लिए एक अच्छी तरह से कानूनी रणनीति की आवश्यकता होती है। कानूनी सुरक्षा को मज़बूत करके और लिंग-संवेदनशील न्यायिक प्रशिक्षण प्रदान करके न्याय किया जा सकता है, जो लैंगिक समानता के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

साहित्यिक कचरा निपटान केंद्र

कटाक्ष

विनोद कुमार विक्की

युवा लेखक

'गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल' की तर्ज पर इन दिनो 'लॉगिन है फेसबुक, कचरा तु डाल' प्रचलन में है।

यह और बात है कि सफाईकर्मी घर पर आकर कचरा निकालने का आग्रह करते हैं, जबकि साहित्य जगत के कचरापोषी बिना किसी आग्रह या पूर्वाग्रह के सदैव साहित्यिक कचरा फैलाने को तत्पर रहते हैं। कचरा उत्पादन के साथ-साथ कचरा प्रसार में भी इनकी महती भूमिका होती है। सोशल मीडिया के अनंत किलोमीटर तक के दायरे में नजर उठाकर देख लीजिए, आपको प्रति पाठक पौने दो हजार लेखक नजर आ जाएंगें। हर कोई दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा का सामंजस्य स्थापित कर लिखने में मस्त और दिखाने में अस्त-व्यस्त है अर्थात साहित्यिक कचरा उत्पादन केन्द्र को प्रोत्साहित करने में तन्मयता से लगे हुए हैं। आत्ममुग्धता की सब्सिडी पर कचरा प्रोडक्शन करने वाले साहित्योद्योग के पूँजीपतियों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या उत्पादन कर रहे हैं? उन्हें तो महज क्वांटिटी से सरोकार है क्वालिटी से नहीं! साहित्योद्योग के कचरा सेठ निर्माण के साथ ही ऐसे साहित्यिक उत्पादों को फेसबुक की दुकान, व्हाट्सएप एजेंसी, वेबसाइट आदि पर प्रसारित कर देते हैं।

इन दिनों साहित्य कबाड़ इंड्रस्ट्रलिस्ट के रूप में महिला उद्यमी काफी सफल मानी जाती हैं। दो-चार लाइन की तुकबंदी पर अपने पोज वाली तस्वीरें डालकर सोशल मीडिया पर महफ़िल लूट लेती हैं। फेसबुक पर इनकी अंगड़ाई भी कालजयी होती है। सुबह-सुबह इनके द्वारा शायरी/गजल/व्यंग्य के रूप में कचरा बिखेरने मात्र की देर है, उन उत्पादों पर पाठक से रिएक्शन मिले ना मिले, लेकिन लाइक, कमेन्ट्स के साथ साहित्यकार मित्रों की लंबी दादुर फौज बिना बरसात ही इनके पोस्ट पर टर्र-टर्र करते हुए 'वाह-वाह,बहुत खूब,क्या बात,शानदार,जबरदस्त' आदि का सम्मोहनीय राग अलाप कर अघाते नहीं है।

कचरा निपटान के तहत कचरा की गुणवत्ता के आधार पर जिस प्रकार सड़ने-गलने वाले कचरे को हरे डस्टबिन में और ठोस कचरा को नीले डस्टबिन में डालने की परिपाटी है, ठीक उसी तरह साहित्यिक कचरा में समसामयिक और प्रासंगिक के तर्ज पर कचरा फैलाने का चलन है। समसामयिक कचरा को फेसबुक या दैनिक जोगिड़ा,सांध्य-सवेरा टाइम्स आदि में डिस्पोजल (छपने) हेतु डाला जाता है, तो कालजयी कचरा को मासिक हुलाला,छपास भारती? आदि मैगजीन में निष्पादन हेतु भेजा जाता है।

ऐसे कलमवीरों की प्रेषित रचनाएँ, जब बिना संपादन या प्रूफ रीडिंग के कापी-पेस्ट के साथ किसी इलाका एक्सप्रेस वाले समाचार पत्र या पत्रिका में प्रकाशित होती है, तो इनकी रचना मात्र के छप जाने से वह पत्र-पत्रिका रातों रात इंटरनेशनल एक्सप्रेस में कन्वर्ट हो जाता है और संबंधित पत्रिका राष्ट्रीय, ख्यातिनाम,बहुचर्चित एवं सर्वाधिक लोकप्रिय हो जाती है। (डिसक्लेमर- फेसबुक पर कचरा कटिंग को फैलाते वक्त कचरा सेठ की ऐसी स्वघोषित टिप्पणी होती है) फिर इन कचरा सामग्री को फेसबुक मंडी में रखा जाता है।तत्पश्चात दैनिक ग्राहक (फेसबुक मित्रो) एवं कचरा सेठ(लेखक) के बीच बधाई और धन्यवाद का विनिमय-वितरण दिन भर निर्बाध रूप से चलता रहता है। इन साहित्यिक कचरा को लांच करने वाली कंपनी के जो मालिक (संपादक) होते हैं, उन मालिकों के लिए कचरा सेठ द्वारा तत्काल ही शुक्रिया रूपी शब्दों का भुगतान कर दिया जाता है। जिस कंपनी (पत्र या पत्रिका के अंक) ने इनके कचरे (रचना) का निपटान (प्रकाशित) किया उस कंपनी को सर्वश्रेष्ठ और कंपनी के परम आदरणीय मालिक (संपादक) को सदाशयी,मिलनसार और मार्गदर्शक की संज्ञा देते हुए आत्मीय उद्गार प्रकट किया जाता है।

फेसबुक,सोशल मीडिया पर सहिष्णुता वाला ऐसा प्लेटफार्म है, जहाँ हर तरह की मालगाड़ी का ठहराव होता है। ज्यों ही इस प्लेटफार्म पर यह अपने मालगाड़ी का माल गिराते हैं तत्काल ही इनके कचरा उत्पाद पर लाइक की बोहनी हो जाती है। वैसे कचरा सेठ भी लोन लेकर दूसरे की माल की खरीदारी करते हैं अर्थात दूसरे की पोस्ट पर नियमित अंगूठा चिपकाते हैं, बदले में इनके कचरा प्रोडक्ट पर भी कुछ अंगूठा दान लाजिमी है। मजे की बात है कि फेसबुक पर कभी कोई इन कचरा सेठ के कचरा प्रोडक्ट(रचना) को कचरा कहने की जहमत नही उठाता और इस प्रकार आभासी दुनिया में कचरा सेठों के बीच साहित्यिक सहिष्णुता और आपसी भाईचारा सदैव कायम रहता है।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पी.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस प्रा. लि., राउखेड़ी, देवास रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 662, साईं कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक - उमेश त्रिवेदी
संपादक (म.प्र.) -विनोद तिवारी
कार्यकारी प्रधान संपादक - अजय बोकिल
स्थानीय संपादक - हेमंत पाल
प्रबंध संपादक - अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

अच्छी पड़ी डांट ... मुझे आया मजा

व्यंग्य

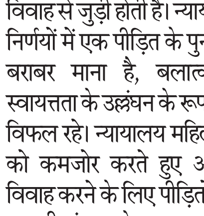

राजेंद्र बज

लेखक व्यंग्यकार हैं।

बचपन के वे दिन भी क्या दिन थे ...., जब हमारा भाई बहनों या मित्रों से किसी बात को लेकर विवाद हो जाता था। हमारे साथ मारा कुटी हो जाती या हमें बुरी तरह चिढ़ा दिया जाता। ... और हम रोते बिलखते हुए अपने माता पिता से अपने प्रताड़ित होने को लेकर फरियाद करते। तब तत्काल प्रभाव से शिकायत का संज्ञान लिया जाता। इसके आगे होता यह कि जिसने हमें मारा ठोका या चिढ़ाया, उसे जमकर डांट फटकार करते हुए आड़े हाथों लिया जाता। हमें 'अच्छी पड़ी डांट, मुझे आया मजा' वाली फीलिंग हुआ करती थी। एकाएक हम रोना बिलखना भूल जाया करते थे और मुखमंडल पर मुस्कुराहट बिखर जाती थी। अंतर्मन में विजेता भाव जागृत हो जाया करता था।

लेकिन अब जब पचपन पार कर चुके, यह क्रम आज भी लगातार जारी है। अब मुख्य पात्र तो हम ही हैं लेकिन अन्य पात्र बदल गए हैं। आज भी हमारी ठुकाई पिटाई होती है और हमें चिढ़ाया जाता है। लेकिन ठोकने पीटने और चिढ़ाने वाले चेहरे बदल गए हैं। राजनीतिक विकृति, प्रशासनिक लापरवाही, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा सामाजिक परिवेश में घटित होने जघन्य अपराधों के चलते जाहिर तौर पर तो नहीं लेकिन भीतर ही भीतर हम लगातार रोने बिलखने को विवश रहा करते हैं। ऐसे में कभी हम न्यायिक शरण में जाते हैं, कभी ऊंचे पद पर विराजित शख्सियत से फरियाद करते हैं तो कभी इस बात का इंतजार करते हैं कि मीडिया द्वारा हमारी स्थिति का संज्ञान लिया जाए।

इसके चलते समय-समय पर न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के कर्णधार हमें प्रताड़ित करने वाले संबंधित पक्ष को जमकर लताड़ लगाते हुए उसका कान पकड़कर मरोड़ दिया करते है। जिसके चलते लाखों करोड़ों जलते हुए कलेजे को काफी हद तक ठंडक महसूस होती है। इन्हें ऐसा लगने लगता है मानो अब तक जो हुआ हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जैसा कि हुआ था। एक प्रकार की ऐसी सांत्वना मिला करती है कि आदमी का रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो है - रंग जीवन में नया लाओ रे। अब इसके आगे अंतिम परिणाम क्या होता है, चाहे यह सवाल सवाल ही रह जाए, लेकिन कुछ नहीं से कुछ होने का संतोष होता है।

जब-जब भी कहीं से किसी अथॉरिटी को जमकर फटकार लगती है तब सच कहूं, इसके चलते वही बचपन वाली फीलिंग, 'अच्छी पड़ी डांट मुझे आया मजा' आती है। मन मयूर आनंद से खिल उठता है। मन इतना प्रसन्न हो जाता है कि मानो वह समस्या जड़मूल से समाप्त हो गई हो। अब यह अलग बात है कि ढाक के वही तीन पात हुआ करते है। लेकिन यह भी तो सच है कि तपते रेगिस्तान में अगर दो बूंद पानी की मिल जाए, तो भी क्या यह कम है ! वैसे भी आदमी को क्या चाहिए ? यह बात भी कोई कम नहीं कि उसे अभिव्यक्ति की भरपूर स्वतंत्रता है। इसके चलते उसका रोना-बिलखना, चीँखना चिल्लाना भी निर्बाध गति से जारी रह सकता है।

सोचो कभी इस पर भी रोक होती, कितना मन मारकर जिंदगी को घसीटना पड़ता ! दरअसल निष्ठुर हृदय तो वह होता है जो मारता है और रोने भी नहीं देता। हमारे लिए यह कोई छोटी बात नहीं है कि रोने कलपने की हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। जब हम यह पढ़ते सुनते या देखते हैं कि हमें काफी ऊंचा लगने वाला ऊंट आखिर पहाड़ के नीचे आया है, एकाएक हमारा कद बहुत ऊंचा हो जाता है। अब यह अलग बात है कि ऊंट तो ऊंट होता है, वह बकरियों के झुंड में भी सबसे ऊंचा ही होता है। रहा सवाल पहाड़ का, तो उसके पट्टी पहाड़े का क्या कहना! वह जानता है कि उसकी ऊंट पर बादशाहत तभी तक बरकरार है - जब तक कि ऊंट उसका कहा मानता और सुनता है।

दिल्ली में बीजेपी

वेद विलास उनियाल
वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक

अब दिल्ली को नए सिरे से संवारने की चुनौती

दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं की रैली में दिल्ली को आधुनिक शहर बनाने का उद्घोष किया। साथ ही इस बात को जोर देते हुए इसे मोदी की गारंटी से भी जोड़ा। उन्होंने इस बात का संकल्प लिया कि यमुना को दिल्ली की पहचान बनाया जाएगा। बीजेपी ने दिल्ली के चुनावी रण को जीतने के लिए जिन मुद्दों को धार दी, उनमें 'आप' शासन के कथित भ्रष्टाचार के साथ दिल्ली की अव्यवस्था को सामने रखा।

आखिरकार शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता के नाम पर ही दिल्ली के नेतृत्व के लिए सहमति बन गई। बेशक, वे विधायक के तौर पर पहला चुनाव जीती हो, लेकिन दिल्ली की सियासत में वे मंजी हुई नेता है। आरएसएस की पृष्ठभूमि में रहकर, एबीवीपी के सानिध्य में दौलतराम कॉलेज की सचिव और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष बनना उनके छात्र जीवन के संघर्ष को दर्शाता है। यह उनका हौसला है, कि दो बार विधानसभा का चुनाव और दिल्ली मेयर के चुनाव में पराजय देखने के बाद भी उन्होंने अपना मनोबल नहीं खोया।

इसी का ही नतीजा है कि इस बार वे चुनाव भी जीती और अब दिल्ली की कमान उनके हाथ में आई। वे दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं और इस दौर में बीजेपी की जिन जिन राज्यों में सरकार है वह पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया। दिल्ली का नेतृत्व हाथ में लेते हुए उनके सामने कई चुनौतियां हैं। निश्चित विकास की एक बड़ी रेखा खींचना उनके लिए कसौटी हैं।

बीजेपी दिल्ली के मतदाताओं तक यह संदेश पहुंचाने में सफल रही, कि देश की राजधानी का यह स्वरूप और बेहतर होना चाहिए। बेशक दिल्ली के पॉश इलाकों को छोड़ दिया जाए, तो दिल्ली के दूसरे फैले इलाकों और बस्तियों को और बेहतर बनाने की जरूरत हैं। दिल्ली को लेकर सभी सियासी पार्टियां अपने-अपने स्तर पर अपनी उपलब्धियां और कामकाजों को गिनाती हैं। लेकिन, तरह-तरह के दावों के बावजूद दिल्ली पानी और बिजली के संकट से जूझती आई है। बढ़ता प्रदूषण दिल्ली का स्थायी संकट है। ऐसी स्थितियों में बीजेपी ने मतदाताओं को इस भरोसे में लिया है कि केंद्र में मोदी का नेतृत्व और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार दिल्ली को बदलने में सक्षम है। इसे समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के बाद अपने संकल्पों को फिर दोहराया है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में सियासी दलों के लिए मुद्दे स्पष्ट थे। दिल्ली में आप सरकार को घेरने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बड़े दलों ने दिल्ली से जुड़ी समस्याओं को सामने रखते हुए बदलाव के नाम पर वोट मांगे। दिल्ली में जब स्वयं 'आप' पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे दिल्ली की जनता से किए कुछ वादे पूरे नहीं कर पाए तो विपक्ष के प्रचार अभियान को और गति मिल गई। केजरीवाल ने जिन वादों को पूरा न होने की बात कही उनमें दिल्ली की सड़कों को बेहतर न बना पाने के अलावा यमुना की स्वच्छ न कर पाने की बात अहम थी। विपक्ष खासकर बीजेपी के लिए यह अच्छा खासा प्रचार का मुद्दा बना। केजरीवाल के उस बयान को सोशल मीडिया में प्रचारित किया गया, जिसमें उन्होंने यमुना को स्वच्छ न करने पर राजनीति छोड़ देने की बात कही थी।

केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से इन समस्याओं को दूर करने के लिए और पांच साल की सत्ता दिलाने का आह्वान किया। इसी बात को लपकते हुए बीजेपी ने अपना चुनावी नारा दिया कि 'बहाने नहीं बदलाव चाहिए।' उधर, चुनावी प्रचार के अभियान के शुरुआती दौर में ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली सभा में 'आप' के नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि वह तो अपने मंत्रियों के साथ प्रयागराज में गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन, केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाकर देखें। इस एक लाइन में ही कई लाइनें खींची गई थी। योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से यूपी में बीजेपी सरकार के कामकाज को दिल्ली सरकार से तुलना करके मतदाताओं को झकझोरने की कोशिश की थी। उनका स्पष्ट संदेश था कि दिल्ली में जिस बदलाव की अपेक्षा की जा रही है, उसे एनडीए सरकार के जरिए ही संभव है। दिल्ली में तमाम दिक्कतों पर कांग्रेस ने भी आप को घेरा। लेकिन, मतदाताओं ने बीजेपी को 27 साल बाद फिर अवसर देने का मन बनाया।

कांग्रेस का कमजोर संगठन और अपनी स्पष्ट चुनावी व्यूह रचना न होने से मतदाताओं के पास बीजेपी के तौर पर खुला विकल्प था। जहां कांग्रेस को लेकर आखिरी मतदाताओं में असमंजस था, वहीं बीजेपी दिल्ली में जीत हासिल करने के लिए पूरी सियासी रणनीति के साथ थी। दिल्ली चुनाव में मतदाताओं को

साधने के लिए बीजेपी ने लंबी तैयारी की थी। चुनाव आते आते हर कदम पर बीजेपी फ्रंट फुट पर दिखी। दिल्ली की समस्याओं और अपेक्षाओं को समझते हुए बीजेपी ने अचूक रणनीति अपनाई। जहां एक तरफ आठवें वेतन आयोग की स्थापना और केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग को विशेष राहत दी गई, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की एक भी झुग्गी न टूटने का आश्वासन देकर कमजोर वर्ग को भी साधने की कोशिश की। इन मुद्दों के चुनाव परिणामों पर अपने असर रहे होंगे। लेकिन, दिल्ली के लोगों के सामने सबसे बुनियादी समस्या तो पानी, बिजली, सड़क और लगातार बढते प्रदूषण की रही है।

इसलिए जब बीजेपी के शीर्ष नेता दिल्ली को आधुनिक शहर बनाने का संकल्प दोहरा रहे हैं, तो निश्चित की इन समस्याओं के निराकरण के बाद ही देश की राजधानी इस स्वरूप में होगी। यह आसान चुनौती नहीं, लेकिन संकल्प को धरातल पर उतारा जाए तो दिल्ली का नजारा कुछ और हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी अपने शासित राज्यों के मॉडल दिखाकर दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहती है कि जैसे बनारस, प्रयागराज या अयोध्या को बदला गया है। यही नहीं दिल्ली के आसपास के क्षेत्र भी तेजी से बदलते हुए दिख रहे हैं, वैसे ही दिल्ली पर भी डबल इंजन की सरकार अपना फोकस करेगी।

वास्तव में जब हम भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने को तत्पर दिखते हैं, तो देश की राजधानी भी अत्याधुनिक स्वरूप में होनी चाहिए। दिल्ली का आशय केवल वह क्षेत्र नहीं जो चमकता दमकता नजर आता है। दिल्ली के अंदर बस्तियां हैं, गांव हैं, इलाके हैं। इन सबको मिलाकर दिल्ली बनती है। यहां लोग जिन समस्याओं को झेलते हैं वह चमकती राजधानी के लक्षण नहीं है। पानी के लिए लंबा कतारें लगती है। पानी की बाल्टियों के साथ लोग झगड़ते नजर आते हैं। टैंकर लॉबी की मनमानी चलती है। बस्तियों में कूडों के अंबार दिखते हैं। बिजली की समस्या है। पराली कहीं भी जले, लेकिन दिल्ली का आकाश धुंआ धुआ हो जाता है। सड़कों में गड्ढे नजर आते हैं। पहली बरसात में ही दिल्ली में सड़कें तालाब बन जाती हैं। दुनिया में दिल्ली प्रदूषण की सूची में टॉप पर नजर आती है। झुग्गियों बस्तियों की अपनी समस्याएं हैं। वाहन सड़कों पर रेंग रेंगकर आगे बढते हैं। सड़कों से लेकर सीवर सिस्टम तक दिल्ली का समस्याओं का अंबार है।

स्वास्थ्य शिक्षा सेवाओं की हालात भी नजर आते हैं। विपक्ष के चुनावी मेनिफेस्टो को देखे तो इन बातों का ही उल्लेख दिखता है। 'आप' ने अपनी उपलब्धियों को गिनाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन, दिल्ली की जनता ने बदलाव ही चाहा। स्पष्ट है कि दिल्ली की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई है। ऐसे में नई सरकार के सामने असल चुनौतियां सामने खड़ी है। इसके लिए दूरबीन की जरूरत नहीं है। चुनावी मेनिफेस्टो से निकलकर बीजेपी सरकार को धरातल पर काम करना होगा। खासकर ऐसी स्थिति में जब कोई और नहीं प्रधानमंत्री मोदी यह कह चुके है, कि दिल्ली को दुनिया की आधुनिक राजधानी बनाना उनका संकल्प हैं। जब वह ऐलान कर चुके हो कि दिल्ली की पहचान यमुना मैय्या से होगी।

ऐसे में गौर किया जाना चाहिए ऐसे में गौर किया जाना चाहिए कि दुनिया की बेहतरीन राजधानियों में गिने जाने वाले लंदन में टेम्स, ऑस्ट्रिया के विएना में डैन्यूब पेरिस में सीन नदी क्रिस्टल की तरह चमकती है। एक बार देहरादून के शहर के एक स्कूल में बच्चों का दल पेरिस गया था। वहां से लौटकर एक बच्चे ने कहा था कि काश दिल्ली की यमुना का जल भी सीन नदी की तरह होता। गौरतलब है कि लंदन में टेम्स नदी भी एक समय प्रदूषित नदियों में थी। लेकिन, नदी को साफ सुथरा करने का प्रयास किया गया। लंदन शहर की सड़कें कभी बरसाती पानी से भर जाती थी। बाद में सीवरेज सिस्टम को सुधारा गया। वास्तव में किसी शहर की पहचान उसके करीब बहती नदी से भी होती है। ऐसे में यमुना का महत्व केवल बहती जलधारा से ही नहीं, इसका आध्यात्मिक सांस्कृतिक महत्व भी है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधन में यमुना के मंत्रों का उद्घोष करते हैं और अपने भाषण का अंत भी यमुना के जयकारे से करते हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली शहर में यमुना को स्वच्छ करने का अभियान जोर पकड़ेगा। इसी तरह दिल्ली को चमकता शहर बनाने की चुनौती है। निश्चित अगर डबल इंजन सरकार ने इसका संकल्प लिया है तो उनके पास इसके लिए चार्ट भी होगा। दिल्ली की जनता यह सब धरातल पर उतरते हुए देखना चाहती है।

दिल्ली का अपना एक इतिहास है। दिल्ली का अपना सौंदर्य, पुरातत्व संस्कृति और विरासत है। दिल्ली को अत्याधुनिक शहर के रूप में सामने लाने की जो चुनौतियां हैं, उसके लिए धरातल पर काम करना होगा। इसी क्रम में मेट्रो के विस्तार, सड़क पुलों के निर्माण की अपेक्षा की जा रही है, निश्चित डबल इंजन की सरकार दिल्ली को जो स्वरूप देगी आगे की सियासत पर उसका सीधा असर पडेगा। वहीं दिल्ली में अपनी जनाधार को पाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस पर भी एक सजग विपक्ष की अपेक्षा बनी है। 'आप' पार्टी को भी अब नई रणनीतियों के साथ सामने आना होगा। उसके पास दिल्ली में संगठन है 22 विधायक हैं। सकारात्मक विपक्ष के तौर पर वह सामने दिख सकती है।

दिल्ली को केंद्र राज्य की डबल इंजन सरकार की कोशिश अपनी जगह होंगी लेकिन दिल्ली नगर निगम की भूमिका का भी अपना महत्व है। यह स्पष्ट है कि दिल्ली के लोगों के मन में दिल्ली को चमकता शहर देखने की कल्पना है। 27 साल बाद दिल्ली की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ अच्छे बहुमत के साथ बीजेपी को सरकार सौंपी है। कहा जा सकता है कि मोदी की गारंटी पर भी वोट पड़े हैं। देखना होगा कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली का स्वरूप किस तरह बदलता है। दिल्ली में रेखा गुप्ता के नए नेतृत्व से कई तरह की अपेक्षाएं हैं। यह भी स्पष्ट है कि कामकाज का आकलन में लोग मोदी की गारंटी को ही कसौटी पर ही परखेंगे।

अभियान

प्रीतम लखवाल

एक लाख 19 हजार 759 पेड़ों को बचाने की जद्दोजहद

अपना सबकुछ न्योछावर करके भी बदले में कुछ नहीं चाहती। वह केवल इतना चाहती है कि जो मनुष्य के भीतर है। वह प्रकृति में भी तो है। वह है वजूद। इंसान की जिंदगी पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। अगर उसे किसी ने नुकसान पहुंचाया तो इंसान का वजूद धूल भी नहीं रहेगा। राजस्थान प्रांत का बारां जिला इन दिनों खासा चर्चा में है।

यह निर्विवादित है कि प्रकृति से हम हैं। अगर प्रकृति पर आघात होगा तो हम कहां के रहेंगे। इसे साबित करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। एक पौधे को पेड़ बनने में काफी वक्त लगता है। जैसे एक बालक जब युवा हो जाता है तब जाकर एक पौधा पेड़ का दर्जा प्राप्त करता है। प्रकृति हमें कई नेमतों से नवाजती है। अपना सबकुछ न्योछावर करके भी बदले में कुछ नहीं चाहती। वह केवल इतना चाहती है कि जो मनुष्य के भीतर है। वह प्रकृति में भी तो है। वह है वजूद। इंसान की जिंदगी पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। अगर उसे किसी ने नुकसान पहुंचाया तो इंसान का वजूद धूल भी नहीं रहेगा। राजस्थान प्रांत का बारां जिला इन दिनों खासा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए नहीं कि वहां कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है, लेकिन जो होने जा रहा है उसे रोकने के लिए समूचे जिले में अभियान की ऐसी आंधी चल रही है, जिसे और अधिक गति की जरूरत महसूस हो रही है।

उल्लेखनीय यह है कि बारां जिले के शाहाबाद में सरकार एक बहुत बड़ा उपक्रम लगाने जा रही है। विकास के नाम पर इस शाहाबाद के वन क्षेत्र के एक लाख 19 हजार 759 पेड़ों की बलि देने की तैयारी कर ली गई है। इन पेड़ों को काटकर यहां वह कारखाना अस्तित्व में आएगा जो विकास का प्रतिनिधित्व तो करेगा, लेकिन इस क्षेत्र की जनता से उनकी हिस्से की सांसों को भी छीन लेगा। करीब तीन महीने से बारां जिले में इंटेक बारां चेप्टर की ओर से संपूर्ण जिले में इन एक लाख 19 हजार 759 पेड़ों को बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इंटेक बारां चेप्टर के कन्विनर जितेंद्र शर्मा पम्मी के नेतृत्व में स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि से लेकर रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारियों ने जनजागृति की मशाल थाम रखी है। एक लाख से अधिक पेड़ों की लाश पर विकास का ढांचा खड़े करने वाले सरकार के नुमाइंदों की आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई है। इंटेक बारां चेप्टर के कन्विनर जितेंद्र शर्मा पम्मी के अथक प्रयासों से अभियान ने गति तो पकड़ी है, लेकिन इसे राज्य व्यापी नहीं देश व्यापी अभियान बनाने की जरूरत है। बारां जिले के गांव-गांव, मजरे-मजरे, टोला-टोला और शाहाबाद के जंगल में रहने वाले वनवासियों तक यह अभियान पहुंचा। अब जरूरत है कि इस अभियान को देश के कोने-कोने से समर्थन मिले तो इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की बलि को रोका जा सकता है।

मुद्दा

रमेश सर्राफ धमोरा
लेखक पत्रकार हैं।

विकसित हो भीड़ नियंत्रण का प्रभावी तंत्र

देश में हम आए दिन भीड़ में भगदड़ मचने से कई लोगों के मरने की खबरें पढ़ते रहते हैं। हाल ही में महाकुंभ स्नान के दौरान प्रयागराज में भीड़ में भगदड़ के चलते 37 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही नईदिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वालों की भीड़ में अचानक भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई थी। यह दोनों ही दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व दुखद है।

देश में भगदड़ में मरने वालों की सूची बहुत लंबी है। सभी को पता है कि जहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित होगी वहां कभी भी भगदड़ मचने की स्थिति पैदा हो सकती है। मगर अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन पाई है जिससे भगदड़ की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होने पाए। सरकारी भी भगदड़ होने के बाद उसको रोकने के ढोल पीट कर कुछ समय बाद शांत बैठ जाती है। मगर ऐसा कोई स्थाई तंत्र विकसित नहीं किया जाता है। जिससे भगदड़ की स्थिति होने से पहले ही सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट मिले और वह उन पर नियंत्रण कर सके। भगदड़ भीड़ प्रबंधन की असफलता की स्थिति में पैदा हुई मानव निर्मित आपदा है। भगदड़ प्रायः भीड़ भरे इलाको में किसी अफवाह के कारण भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण भी यह आपदा पैदा होती है। इसमें संपत्ति से अधिक जान की क्षति होने की संभावना रहती है। भीड़ दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के वैश्विक डेटाबेस के मुताबिक सन 2000 के बाद से भारत में 50 से ज्यादा विनाशकारी सामूहिक समारोहों में दो हजार से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इन दुर्घटना को देखते हुए प्रभावी भीड़ प्रबंधन तंत्र विकसित करने की बहुत जरूरत महसूस की जा रही है। खासकर कुंभ जैसे बड़े आयोजनों में इसकी काफी जरूरत महसूस होती है।

भगदड़ बेहद खतरनाक और घातक स्थिति होती है। किसी भी जगह पर जब भीड़ उसकी क्षमता से अधिक हो जाती है और लोगों के पास निकलने का रास्ता नहीं होता है। भीड़ की वजह से लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में किसी तरह की अफवाह या दुर्घटना होने पर भीड़ बेकाबू हो जाती है। इसे भीड़ में हलचल भी कहा जाता है। इसकी वजह से ही भगदड़ की स्थिति बनती है।

इसी तरह भीड़ में हलचल का मतलब भीड़ का बेतरतीब तरीके से एक से ज्यादा दिशाओं में एक ही समय में आगे बढ़ना है। ऐसे में लोगों को चलने के लिए जगह कम होती है वो एक-दूसरे के बीच दब जाते हैं। जब लोग एक-दूसरे से बहुत नजदीक होते हैं तो 'फोर्सेज का ट्रांसमिशन' यानी बल का संचरण हो सकता है। इस फोर्स ट्रांसमिशन को आपने भी कभी न कभी तब महसूस किया होगा जब आप एक बहुत भीड़-भाड़ वाली किसी लाइन में खड़े हुए होंगे। जब पीछे से अचानक धक्का लगता है तो व्यक्ति खुद भी उस धक्के को अपने से आगे खड़े व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे में अपना संतुलन बनाए रखना और अपने पैरों पर खड़े रहना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।

ये पहली बार नहीं था जब किसी धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मची हो। इसके पहले भी समय-समय पर भगदड़ मचने की खबरें सामने आती रही हैं। इन घटनाओं में कई लोगों की जान भी चली गई। 27 अगस्त 2003 महाराष्ट्र के नासिक जिले में कुंभ मेले में स्नान के दौरान भगदड़ मचने से 39 लोगों की मौत हो गई थी। 25 जनवरी 2005 को महाराष्ट के सतारा जिले में मंधारदेवी मंदिर में भगदड़ मच गई थी। जिसमें 340 से ज्यादा श्रद्धालु कुचले गए थे। 3 अगस्त 2008 हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी मंदिर में मची

भगदड़ में 162 लोगों की मौत हो गई थी। 30 सितंबर 2008 राजस्थान के जोधपुर शहर में चामुंडा देवी मंदिर में मची भगदड़ में लगभग 250 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 4 मार्च 2010 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कृपालु महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ में 63 लोगों की मौत हो गई थी।14 जनवरी 2011 को केरल के इडुक्की जिले के पुलमेडु में सबरीमाला मंदिर में एक जीप की टक्कर से मची भगदड़ में 104 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 8 नवंबर 2011 को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे हर की पौड़ी घाट पर मची भगदड़ में लगभग 20 लोगों की मौत हो गई थी। 19 नवंबर 2012 को पटना में गंगा नदी पर छठ पूजा के दौरान एक अस्थायी पुल के ढह जाने से भगदड़ मच गई थी जिसमें 20 लोगों की मौत हो गयी थी।

13 अक्टूबर 2013 मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि के जश्न के दौरान भगदड़ मचने से 115 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 3 अक्टूबर 2014 को दशहरे का जश्न समाप्त होने के तुरंत बाद पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मच गई जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई थी। 14 जुलाई 2015 को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में पुष्करम उत्सव के पहले दिन गोदावरी नदी के तट पर भगदड़ मचने से 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 1 जनवरी 2022 को जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई थी। 31 मार्च 2023 को इंदौर शहर के एक मंदिर में रामनवमी के मौके पर एक प्राचीन बावड़ी के ऊपर बनी स्लैब के ढह जाने से 36 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसी तरह रेलवे स्टेशनों पर भी भगदड़ के कारण कई बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। 28 सितंबर 2002 को लखनऊ में बसपा की रैली से वापस घर लौटते समय ट्रेन की छत पर चढ़ने से चार लोगों की करंट लगने से मौत हो गई थी। 13 नवंबर 2004 को नई दिल्ली स्टेशन पर छठ पूजा के दौरान बिहार जाने वाले ट्रेन का प्लेटफार्म अचानक बदलने से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए ओवरब्रिज पर मची भगदड़ में चार यात्रियों की मौत हुई थी। 03 अक्टूबर 2007 को मुगल सराय जंक्शन पर भगदड़ मचने के कारण 14 महिलाओं की मौत हो गई थी। 10 फरवरी 2013 को इलाहाबाद में कुंभ मेला के दौरान रेलवे जंक्शन पर भगदड़ मचने से 38 लोगों की मौत हो गई थी। 29 सितंबर 2017 के दिन मुंबई के एलफिंस्टन रेलवे स्टेशन में बने फुटओवर ब्रिज पर भगदड़ मचने के कारण 22 लोगों की मौत हुई थी। हमारे देश में आए दिन जगह-जगह बड़े-बड़े धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व अन्य कई प्रकार के आयोजन होते रहते हैं। जिनमें हजारों-लाखों लोग शामिल होते हैं। ऐसे ही कार्यक्रमों में जरा सी लापरवाही भगदड़ का कारण बन सकती है। ऐसे में यदि कार्यक्रम के आयोजक सावधानी बरतते हुए भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम करें तभी किसी तरह की दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन व प्रयागराज के महाकुंभ में भी जो भगदड़ की स्थिति पैदा हुई है उसमें प्रशासनिक चूक रही है। एक स्थान पर अधिक भीड़ इकट्ठी होने पर यदि प्रशासन के अधिकारी सतर्कता बढ़ाते तो ऐसी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता था। आगे भी सरकार को चाहिए कि ऐसे किसी भी बड़े आयोजनों के लिए और अधिक पुख्ता व्यवस्था करें। देश में आपदा राहत बल को भी अधिक सशक्त किया जाये ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

कैंसर जागरूकता अभियान आज, निकलेगी विशाल रैली

बैतूल। शिवम सेवा समिति के तत्वावधान में विगत 15 वर्षो से विशाल भंडारा आयोजित किया जाता रहा है। इस संबंध में आयोजन समिति के राकेश (रक्कु) शर्मा ने बताया कि हमारी समिति द्वारा धार्मिक आयोजन के साथ- साथ मानवता के हित में भी कार्य करती रही है। इसी के अंतर्गत आज शनिवार कैंसर जागरूकता अभियान, प्लास्टिक उपयोग मुक्त जिला अभियान रैली चलाई जाएगी, जिसमें प्लास्टिक के गिलास, चम्मच, कटोरी के विक्रेताओं से समिति एवं शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा गुलाब का फूल देकर इनका उपयोग नहीं करने का अनुरोध किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में समिति द्वारा बैतूल में कागज के चाय के कप का अभियान चलाया गया था जो आज तक सफलतापूर्वक चल रहे हैं। समिति ने सभी से उक्त कार्यक्रमों में उपस्थित होने का आग्रह किया।

मंदिर परिसर में हुड़दंग से परेशान वार्डवासी

कलेक्टर से शिकायत, जल सत्याग्रह की चेतावनी

बैतूल। शहर के गर्ग कॉलोनी रामनगर क्षेत्र में स्थित साईं मंदिर प्रांगण में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा वार्डवासियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। हर रात नशे में धुत लोग मंदिर के बाहर हुड़दंग मचाते हैं, और ऊंची आवाज में गाने बजाकर माहौल खराब कर रहे हैं। इस कारण आसपास के लोग, खासकर

महिलाएं और बच्चे, काफी परेशान हैं। बच्चों की परीक्षा की तैयारी भी प्रभावित हो रही है। शुक्रवार को वार्ड की महिलाओं और पुरुषों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वार्ड की बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि रात में मंदिर परिसर के पास माहौल बेहद खराब हो जाता है, जिससे महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। कई बार स्थानीय लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वार्डवासियों का कहना है कि यदि प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता तो वे जल सत्याग्रह करेंगे। उन्होंने जिला कलेक्टर से अपील की है कि साईं मंदिर के आसपास पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो ताकि वार्ड में फिर से शांति बहाल हो सके।

प्रयागराज महाकुंभ के त्रिवेणी संगम से लाया गया जल शहरवासियों को किया वितरित

नर्मदापुरम। प्रयागराज महाकुंभ के त्रिवेणी संगम से पवित्र जल लाकर पूर्व नपाध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल एवं नर्मदापुर युवा मंडल के सदस्यों ने शुक्रवार को नर्मदापुरम के सातरास्ते पर शहर के लोगों को प्रसाद के रूप में वितरित किया। त्रिवेणी संगम का जल 250 एमएल की बॉटल में भरकर वितरित किया गया। इस दौरान 2 हजार

बॉटल जल निःशुल्क वितरित किया गया। श्री खंडेलवाल ने बताया कि महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक आयोजन है। उनके द्वारा त्रिवेणी संगम से जल लाया गया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु देश-विदेश से आकर पुण्यलाभ अर्जित करते है। गंगाजल विशेष रूप से प्रयागराज महाकुंभ जाने में असमर्थ लोगों के लिए भी है। यह लोग त्रिवेणी संगम का जल मिलाकर पुण्य स्नान कर धर्म लाभ अर्जित कर सकते है। सबसे पहले विधि विधान से माँ गंगा का पूजन किया गया। माँ गंगा की आरती की गई फिर सभी को जल वितरित किया गया। इस अवसर पर नर्मदापुर युवा मंडल के विजय दिवोलिया , मनीष परदेशी , दीपक महालहा , रूपेश राजपूत , कमलराव चव्हाण , ललित विनोदिया , विशाल दीवान , अखिलेश निगम , महेंद्र मेषकर , वीरू पटवा , देवेंद्र राठौर , राजू आसरे , पंकज सराठे , हरि सेवरिया सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

साहब नगर के लिए नहीं कम-से-कम जाति और समाज के लिए ही पसीज जाओ...?

नर्मदापुरम। सिटी मजिस्ट्रेट सहित तहसीलदार ने एक दिन पहले न्याय की गुहार कर रहे धरना प्रदर्शनकारियों से जो कुछ सुना शायद अब तक की जा चुकी नौकरी के दौरान तो उन्होंने नहीं सुना होगा। ब्राह्मण समाज जबकि एक जुट होकर अमित दीवान आत्महत्या के मामले में नामजद आठों आरोपियों की गिरफ्तारी चाहता है बस..और पुलिस आठों आरोपियों पर ईनाम घोषित कर उन्हें पकड़ नहीं रही बल्कि हाथों पर हाथ रखे बैठी हुई है, आरोपियों की पुलिस को खबर नहीं जैसा वो कह रही अगर यह सच है तो पुलिस की नौकरी करने का तो कोई हक ही नहीं..! जिन्हें एक ही थाने, एक ही जिले में नौकरी करते करते वर्षों बीत चुके

हैं फिर इन पुलिस कर्मियों का जनहित में जनता सहित सरकार को क्या लाभ..? अपराधियों को संरक्षण देकर तो ये मुख्यालय की फिजा दूषित करवा रहे..!

पुलिस से अब अपराधी नहीं शरीफ डरती हैं। इनका अपराधियों से गठबंधन देख कह सकते है कि पुलिस ही अपराधियों से समाज विरोधी काम करवा कर अपना उल्लू सीधा कर रहे। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट ने मिन्नत कर 24 घंटे का समय मांगकर धरना प्रदर्शन खत्म करवा तो दिया लेकिन पीड़ित परिवार को ऐसी परिस्थिति में क्या ये मदद कर पायेंगे जिसमें पुलिस, प्रशासन राजनीति मेल नहीं खाती। मदद मांगने गए प्रतिनिधि मंडल को उन्होंने अश्वासन तो दिया लेकिन वायदा नहीं निभाया इसका लाभ पुलिस बाखूबी उठा रही बचा प्रशासन तो उसे मामले में सुनना पढ़ रही, जैसे उसने धरना प्रदर्शन कारियों से सुना...?

पिछले साल 20,687 किसानों ने कराया था पंजीयन 20 जनवरी से चल रहा पंजीयन का काम

समर्थन मूल्य : एक माह में गेहूं बेचने सिर्फ 1425 किसानों ने कराया पंजीयन

बैतूल। समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन के लिए किसान अब पंजीयन में रूचि दिखाने लगे हैं। इसका कारण यह भी है कि 10 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन में 175 रुपए बोनस की घोषणा की थी, यानी कि समर्थन मूल्य पर गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल बिकेगा। इस खबर से किसानों में खुशी का माहौल है और अब वे उपार्जन के लिए पंजीयन करवाने में रूचि लेने लगे हैं। इसका प्रमाण यह है कि 6 फरवरी तक जहां पूरे जिले में 368 किसानों ने कही पंजीयन कराया था, वहीं अब पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या 3 से 4 गुणा तक बढ़ गई है यानि 21 फरवरी तक जिले में 1425 किसान गेहूं बेचने के लिए पंजीयन करा चुके है और आने वाले समय में किसानों के पंजीयन संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पंजीयन की अंतिम तारीख 31 मार्च तक तय की है, इस अनुमान से किसानों के पास अभी पंजीयन कराने के लिए काफी समय शेष बचा है। इधर पंजीयन की संख्या में बढ़ोतरी का एक कारण गिरदावरी के काम भी तेजी आना है।

जिलेभर में 6 फरवरी तक थे 368 पंजीयन- जिलेभर में गेहूं उपार्जन के लिए 6 फरवरी तक मात्र 368 पंजीयन ही हो सके थे। जब बोनस देने की बात कही गई तो किसान भी पंजीयन कराने में रूचि लेने लगे। साथ ही गिरदावरी में भी गति आई तो इससे भी पंजीयन पर असर पड़ा। यही कारण है कि 21 फरवरी पंजीयन 1425 किसानों का पंजीयन हो पाया है। सबसे अधिक पंजीयन बैतूल ब्लाक में हुए है। बैतूल ब्लाक में 216 किसानों ने समर्थन मूल्य में गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया है, जबकि घोड़ाडोंगरी ब्लाक में सबसे कम 62 पंजीयन हुए है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे पंजीयन की अंतिम तिथि करीब आ रही है, किसान पंजीयन कराने पहुंच रहे है।

अंतिम चरण में गिरदावरी का काम- जिले में गिरदावरी का काम भी लगभग पूरा होने का है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि गेहूं खरीदी का समय सीमा में पिछले साल के बराबर पंजीयन हो जाएंगे। बता दे कि 28 फरवरी तक गिरदावरी होना है। किसान कितने हेक्टेयर रकबे में खेती कर रहे हैं, इसे पटवारी दर्ज करते हैं। कितने रकबे में गेहूं और कितने में चना और मसूर की बोवनी की है। इसके बाद यह पूरा डाटा राजस्व पोर्टल पर चढ़ जाता है। यहां से यह डाटा ई उपार्जन पोर्टल पर फीड कर दिया जाता है। इसके आधार पर किसानों का पंजीयन किया जाता है।

पिछले साल 20687 ने कराया था पंजीयन- पिछले साल की बात करें तो जिलेभर में 20 हजार 687 किसानों ने पंजीयन कराया था। हालांकि समर्थन पर उपज बेचने वाले किसानों की संख्या कम रही थी। इनमें से केवल 1926 किसान ही उपज लेकर समर्थन खरीदी केंद्रों पर पहुंचे थे। जिनसे करीब 12,600 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई थी। समर्थन मूल्य में गेहूं की खरीदी कम होने के पीछे जानकारों का यह भी मानना है कि खुले बाजार में किसानों को अच्छे दाम मिल जाते है। जिससे किसान समर्थन मूल्य में उपज बेचने पंजीयन तो कराते है, लेकिन उपज नहीं बेचते है। अभी वर्तमान में कृषि उपज मंडी में गेहूं की आवक हो रही है और मंडी में करीब 2800 से 3100 तक गेहूं के भाव किसानों को मिल रहे है।

इनका कहना है

अभी तक 1425 किसानों ने गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया है। पिछले साल 20,687 किसानों का पंजीयन हुआ था। जिसमें से 1926 किसानों ने उपज बेची थी। किसानों को बाजार में अच्छा भाव मिलने के कारण भी किसान समर्थन मूल्य में उपज बेचने नहीं आते है। इस साल मुख्यमंत्री ने गेहूं उपज पर 175 रूपये बोनस देने की घोषणा की है, लेकिन अभी लिखित आदेश नहीं आये है।

- कृष्ण कुमार टेकाम,
जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, बैतूल

20 जनवरी से शुरू है पंजीयन कार्य

जिले में शासन ने रबी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 20 जनवरी से पंजीयन कराने के निर्देश जारी किये है। इन आदेशों के पालन में प्रशासन द्वारा जिले में 72 केंद्रों पर पंजीयन भी शुरू करा दिए। बता दे कि इस वर्ष जिले में 2 लाख 96 हजार हेक्टेयर में गेहूं की रकबा तय किया है। इस वर्ष शासन ने गेहूं का समर्थन मूल्य में 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने 175 रूपये बोनस देने की घोषणा की है। जबकि किसान सोसायटी और कियोस्क सेंटर दोनों जगहों से पंजीयन करा सकते हैं। किसानों को उनके आधार से लिंक बैंक खातों में सीधे भुगतान किया जाएगा। किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। फिर भी अभी तक उम्मीद के मुताबिक किसान केन्द्र नहीं पहुंचे है।

जिले के ब्लाकों में पंजीयन की स्थिति

ब्लाक	गेहूं	चना
बैतूल	216	1
मुलताई	204	1
भैंसदेही	193	3
आठनेर	169	3
प्रभातपट्टन	156	1
चिचोली	145	0
आमला	101	1
शाहपुर	93	0
भीमपुर	86	2
घोड़ाडोंगरी	62	1
कुल	**1425**	**13**

बालाजीपुरम में लाया गया महाकुंभ संगम जल

रविवार को सभी श्रद्धालुओं के लिए बालाजीपुरम में रहेगी कुंभ स्नान की व्यवस्था

बैतूल। प्रयागराज में 144 साल बाद लग रहे महाकुंभ में बैतूल जिले और आसपास के अंचल से काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और संगम स्नान कर पुण्यलाभ अर्जित किया। लेकिन ऐसे लोग भी बहुतायत में हैं जो महाकुंभ में जाकर संगम स्नान करना तो चाहते है? लेकिन समय, साधन, उम्र या आर्थिक संकट के कारण उनका प्रयागराज जाना नहीं हो पाया। अब जब महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान संपन्न होने जा रहा है तो ऐसे लोग मायूस हो रहे हैं। इन लोगों की मायूसी को दूर करने के बालाजीपुरम प्रबंधन सामने आया और सभी श्रद्धालुओं के लिए संगम जल की विशेष व्यवस्था की। इस संबंध में भारत के पांचवेधाम श्री रूकमणि बालाजी मंदिर बालाजीपुरम बैतूल के संस्थापक सेम वर्मा ने बताया कि वे स्वयं और बालाजीपुरम से जुड़े अधिकांश लोग समय-समय पर महाकुंभ प्रयागराज जाकर संगम स्नान कर आएं हैं लेकिन फिर भी काफी संख्या में आम श्रद्धालु, बच्चे महिलाएं और विशेषकर बुजुर्ग संगम स्नान का लाभ नहीं ले पाएं हैं। उनके लिए संगम का ही जल विशेष रूप से बुलवाया गया है। रविवार 23 फरवरी को सुबह 8 बजे विशेष पूजन-अर्चन कर संगम जल के सात कुंडों को बालाजी मंदिर के सामने गंगाकुंड में अर्पित किया जाएगा। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए वहीं स्नान की व्यवस्था रहेगी। महिलाओं और पुरूषों के स्नान की अलग-अलग व्यवस्था रहेगी। साथ ही कपड़े बदलने का इंतजाम भी रहेगा। सभी श्रद्धालु सूर्य को अर्ध्य भी अर्पित कर सकेंगे और पानी में खड़े होकर सूर्य नारायण की आरती भी कर सकेंगे। रविवार को सुबह 8 से लेकर शाम 6 बजे तक स्नान की व्यवस्था रहेगी। श्री वर्मा ने सभी बुजुर्गों से इस बालाजीपुरम संगम स्नान में शामिल होकर पुण्यलाभ उठाने की अपील की है। साथ ही यदि कोई बुजुर्ग अकेला है और आने-जाने में असक्षम है तो बालाजीपुरम कार्यालय में किसी के व्दारा भी सूचित करने पर उनके लाने-ले जाने की निशुल्क व्यवस्था भी मंदिर प्रबंधन व्दारा की जाएगी।

राहुल नाइक हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

8 लोगों ने शराब पिलाकर की थी हत्या

बैतूल। पुलिस ने राहुल नाइक हत्याकांड के मुख्य आरोपी यश राने उर्फ बिल्लू सांडा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 19 दिनों से फरार था। पुलिस ने उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया है। इस मामले में पुलिस पहले ही तीन नाबालिग समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एक महिला समेत दो आरोपी

अभी फरार हैं। कोतवाली टीआई रविकांत डहरिया ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। घटना 31 जनवरी की है, राहुल आरोपी यश की गर्लफ्रेंड को परेशान करता था। इसका बदला लेने के लिए आठ आरोपियों ने योजना बनाई। वे किदवई वार्ड के खंजनपुर के खेत में शराब पी रहे थे। एक आरोपी ने राहुल को फोन कर वहां बुलाया। राहुल के पहुंचने पर उसे जबरन शराब पिलाई गई। फिर उसके सिर पर शराब की बोतल फोड़ दी गई। आरोपियों ने चाकू से उसके गले, छाती और पेट पर 20-25 वार किए। हत्या के बाद शव को खेत के कुएं में फेंक दिया। 2 फरवरी को मालवीय वार्ड में एक कुएं से 26 वर्षीय राहुल की लाश बरामद हुई थी।

बढ़ई समाज की एकता और संस्कृति प्रशंसनीय: वर्षा मालवीय

विश्वकर्मा जन्मोत्सव में वरिष्ठ नागरिकों और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का हुआ सम्मान

बैतूल। चिचोली विकासखंड में भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जिले भर से हजारों की संख्या में समाजबंधु, महिलाएं और गणमान्य नागरिक इस आयोजन में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान विश्वकर्मा जी के पूजन, अभिषेक और महाआरती से हुई, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने बढ़ई समाज की गौरवशाली परंपरा का उत्सव मनाया। कार्यक्रम में चिचोली नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती वर्षा रितेश मालवी, उपाध्यक्ष संजय आंवलेकर, पार्षद ज्योति जीवन पानकर, चिचोली नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष संतोष मालवीय, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल सिंह कुशवाह, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र जैसवाल, आर्य समाज के अध्यक्ष एवं पार्षद रोहित आर्य, विश्वकर्मा बढ़ई समाज समिति जिला बैतूल के अध्यक्ष गणेश प्रसाद मालवी, सारणी समिति के अध्यक्ष राजकुमार मालवी, आमला समिति के संरक्षक नाथूराम विश्वकर्मा, महिला मंडल की जिलाध्यक्ष अर्चना बल्लू मालवी, बैतूल-हरदा क्षेत्र के मनोनीत गौ सांसद युवराज मालवी, श्रीमती पुष्पा विश्वकर्मा राष्ट्रीय सचिव, अशोक मालवी सारणी, समाज समिति जिला प्रमुख बलवीर मालवी, चिचोली समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र मालवी सहित कई प्रमुख समाजसेवी मंचासीन रहे। समारोह में वरिष्ठ नागरिकों और समाज के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। आमला समिति के संरक्षक नाथूराम विश्वकर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि बैतूल जिले में बढ़ई समाज के 16 हजार परिवार निवास करते हैं, जो हर गांव और विकासखंड में बसे हुए हैं। उन्होंने समाज की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज को मजबूती प्रदान करते हैं।

मंदिर निर्माण में हर संभव मदद करने का आश्वासन- चिचोली नगरपंचायत की अध्यक्ष श्रीमती वर्षा रितेश मालवीय ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती के शुभ अवसर पर उपस्थित मातृशक्ति और समाजबंधुओं को बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बढ़ई समाज की एकता और संस्कृति प्रशंसनीय है और समाज की समृद्धि के लिए सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान विश्वकर्मा जी के मंदिर निर्माण में हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया, जिससे समाज में हर्ष और उत्साह का माहौल बना रहा। इस अवसर पर शंकराचार्य जी द्वारा नियुक्त गौ सांसद युवराज मालवी ने अपने उद्बोधन में कहा कि गौ सेवा ही सच्ची समाज सेवा है और इसे समाज के हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाना चाहिए।

पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पुलिस ने पर्दाफाश

देवास। देवास में बीते 12 फ़रवरी को कलमा स्थित पेट्रोल पंप पर हुई लूट की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया साथ ही अपराध में प्रयुक्त कार सहित पांच लाख का माल जप्त किया प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने बताया कि दिनांक 12.02.2025 के रात के करीब 08.30 बजे फरियादी सुमीत पटेल द्वारा माना टोंकखुर्द को सूचना प्राप्त हुई कि कलमा स्थित जियो पेट्रोल पंप पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मुंह पर मास्क लगाये पंप के कैबीन के अंदर घुसकर कट्टा दिखाकर एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट कर नगदी रुपये लेकर मक्सी तरफ भाग गये है। जिसकी सूचना मिलते ही तत्काल थाना प्रभारी टोंकखुर्द श्री आलोक सोनी अपनेबल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे एवं घटनास्थल का सुक्ष्मता से निरीक्षण कर मक्सी तरफ जानेवाले सभी रास्तों पर सपन नाकाबंदी की गई। उक्त अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना टोंकखुर्द में अपराधक्रमांक 51/2025 धारा 309(6) BNS का अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया। घटना की गंभीरताको देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद के द्वारा अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशितकिया गया था। जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री जयवीर सिंह भदोरिया के मार्गदर्शन मेंअनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सोनकच्छ श्रीमती दीपा माण्डवे के निर्देशन में थाना प्रभारी टोंकखुर्द श्रीआलोक सोनी के नेतृत्व में कुल 06 विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम के द्वारातकनीकी, भौतिक एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।जन सामग्री- घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार कीमती करीबन 5 लाख रुपये।

नवीन फ्लोरिन ने दी ग्रामीण क्षेत्र के तीन स्कूलों की बेटियों को सेनेटरी पेड मशीन की सौगात

देवास /मोहन वर्मा । अपने सामाजिक सरोकार के तहत शहर के उद्योग नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल ने जिले के तीन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालीं बालिकाओं के बेहतर स्वास्थ्य और हाइजीन के लिए सेनेटरी वेडिंग मशीने भेंट की। उद्योग के सीएसआर लीड अतुल मौर्य तथा प्रोजेक्ट सहयोगी एक्ट ईव फाउंडेशन अध्यक्ष मोहन वर्मा ने बताया कि जिले के सिरोंलिया उमावि तथा कन्या शाला तथा हरणगांव के उमावि में अध्यनरत 300 सेअधिक बालिकाओं की सुविधा के लिये तीन मशीन तथा 1500 पैड भेंट किए गए ।

कार्यक्रम में अतिथि रूप में नवीन फ्लोरिन की- क्वालिटी ऑफिसर टीना चौहान तथा शिक्षा विभाग के बीईओ अजय सोलंकी थे जिनका स्वागत सिरोंलिया स्कूल में प्राचार्य गिरिजा शंकर एरवाल, मुन्नालाल मालवीय ने किया वहीं हरणगांव में प्राचार्य श्रीराम राठौर ने किया । अतिथियों ने इस अवसर पर कहा कि ग्रामीण स्कूलों में बालिकाओं को कई बार स्वास्थ्य कोलेकर असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ता हैं और सही जानकारी और सुविधा के अभाव में उनके स्वास्थ्य और हाइजीन पर विपरित प्रभाव पड़ता हैं । दी गई सौगात सचमुच एक जरूरी पहल है जिसके लिये नवीन उद्योग तथा ईव फाउंडेशन का अतिथियों एवं स्कूल प्रबंधन ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सिरोंलिया में आशीष चौधरी, सचिन दिवाकर,शकुंतला भारतीय,दीप्ति राजरस, रेखा नरवरिया, नंदिनी पेकरा,कमल एरवाल,राकेश परिहार,देवेन्द्र सिंह बैस, मनीष पवार तथा हरणगांव में उपेंद्र मंडलोई,रोहित खत्री,जनशिक्षक मोहनलाल बारवा उपस्थित थे ।

भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन और भाषाई सद्भावना आवश्यक : कड़ेल

भोपाल। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल में आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक अशोक कड़ेल ने कहा कि भाषायी सद्भावना आवश्यक है। नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और उपयोग की बात कही गई है। मध्यप्रदेश में हिंदी ग्रंथ अकादमी ने भारतीय ज्ञान परम्परा से संबंधित अनेक प्रकाशन किए हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन विद्यार्थियों द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अनुवाद को भी महत्व दिया जा रहा है।

'तकनीकी युग में मातृभाषा का अस्तित्व और चुनौतियां' विषय पर हुई इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में मप्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के मंत्री संचालक कैलाशचंद्र पंत शामिल हुए। पंत ने कहा कि आज यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भाषाओं के विकास में तकनीक हावी न हो जाए और हम तकनीक के गुलाम न हो, बल्कि तकनीक के स्वामी हों। भोगवादी संस्कृति संघर्ष बढ़ा देती है। आज यह जरूरी है कि हम अपनी ज्ञान परम्परा और समृद्ध संस्कृति को महत्व दें, तभी प्रकृति से भी जुड़ सकेंगे।

विश्वविद्यालय के कुलगुरू प्रोफेसर खेमसिंह डहेरिया ने कहा कि शीघ्र ही विभिन्न भाषाओं का संयुक्त कोष प्रकाशित किया जाएगा। मध्यप्रदेश में चिकित्सा और अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों के हिंदी में प्रारंभ होने से हिंदी का प्रचार बढ़ा है। विभिन्न भाषाओं की श्रेष्ठ पुस्तकों का अन्य भाषाओं में अनुवाद भी जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस का आयोजन यूनेस्को द्वारा की गई पहल है, जिसका हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजन किया जा रहा है।

कार्यक्रम के वक्ताओं में सिंधी भाषा के प्रतिनिधि के रूप में अशोक मनवानी और कविता इसरानी ने हिस्सा लिया। श्रीमती इसरानी ने सिंधी भाषा के उत्पत्ति, विकास, विभिन्न लिपियों के उपयोग और विभाजन के कारण भाषा संरक्षण में उत्पन्न समस्याओं पर रोशनी डाली। मराठी भाषा के प्रतिनिधि भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी अनिल निगुडकर और विश्वविद्यालय के कुल सचिव शैलेन्द्र जैन ने भी विचार व्यक्त किए।यह संगोष्ठी राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित की गई। संगोष्ठी में भाषा विकास परिषद के निदेशक रवि टेकचंदानी के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी के ताप विद्युत गृहों ने हासिल किया 90.74 प्रतिशत पीएलएफ

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के चार ताप विद्युत गृहों ने 19 फरवरी को 90.74 प्रतिशत प्लांट लोड फेक्टर (पीएलएफ) अर्जित कर अब तक का सर्वश्रेष्ठ दैनिक पीएलएफ का रिकार्ड बनाया। इससे पूर्व पॉवर जनरेटिंग कंपनी का सर्वश्रेष्ठ दैनिक पीएलएफ 85.03 प्रतिशत था, जो कि 7 वर्ष पूर्व 19 अप्रैल 2018 को अर्जित किया गया था। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नीरज मंडलोई ने चारों ताप विद्युत गृहों के अभियंताओं व कार्मिकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। उन्होंने आशा जताई कि भविष्य में भी विद्युत उत्पादन के नए रिकार्ड कायम होते रहेंगे।

दिनांक 19 फरवरी को जब मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के 4 ताप विद्युत गृहों द्वारा दैनिक 90.74 प्रतिशत पीएलएफ का रिकार्ड बनाया गया, तब इनका समग्र विद्युत उत्पादन 99.52 मिलियन यूनिट दर्ज किया गया। पॉवर जनरेटिंग कंपनी के चारों ताप विद्युत गृह की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता 4570 मेगावाट है।

दिनांक 19 फरवरी को 210 मेगावाट क्षमता के अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई ने 4.94 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करते हुए 98.06 प्रतिशत पीएलएफ हासिल किया। 500 मेगावाट क्षमता के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी ने 11.80 मिलियन यूनिट दैनिक उत्पादन करते हुए 98.32 प्रतिशत पीएलएफ, 1340 मेगावाट क्षमता के संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंगपुर ने 25.71 मिलियन यूनिट उत्पादन करते हुए 79.95 पीएलएफ व 2520 मेगावाट क्षमता के श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह दोंगलिया ने 57.07 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करते हुए 94.36 प्रतिशत पीएलएफ अर्जित किया।

जर्मनी जीआईएस-2025 में 'पार्टनर कंट्री' के रूप में होगा शामिल

भोपाल (नप्र)। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल में जर्मनी 'पार्टनर कंट्री' के रूप में सहभागिता करेगा। 24 एवं 25 फरवरी 2025 को भोपाल में आयोजित समिट में कॉन्सुल जनरल श्री अचिम फेबिग सहित इंडो-जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स और जर्मन इंडियन इनोवेशन कॉरिडोर के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने म्यूनिख, जर्मनी के दौरे में वहाँ के सीआईआई एवं जर्मन इंडियन इनोवेशन कॉरिडोर-सेंट्रल इंडिया के समन्वय से जर्मन निवेशकों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जर्मन पैवेलियन स्थापित किया जाएगा। इसमें इंडो-जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में भारत-जर्मनी सहयोग के अवसरों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें मध्यप्रदेश सरकार और इंडो-जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं जीआईआईसी-सीआई के बीच एक एमओयू (समझौता ज्ञापन) हस्ताक्षरित किया जाएगा। यह समझौता मध्यप्रदेश में सतत और दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए होगा, जिसमें जर्मन कंपनियाँ विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों में भागीदारी करेंगी।

जर्मनी की कंपनियाँ मध्यप्रदेश में करेंगी निवेश- मध्यप्रदेश में रासायनिक, फार्मा और हार्डवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पहले से कई जर्मन कंपनियाँ कार्यरत हैं। अब सूचना प्रौद्योगिकी, ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेयरी फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीप टेक्नोलॉजी और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्रों में भी जर्मन कंपनियाँ निवेश करने की इच्छुक हैं।

जर्मन पैवेलियन में होगा सामाजिक और आर्थिक विकास परियोजनाओं का प्रदर्शन- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जर्मन पैवेलियन के माध्यम से ग्रीन एनर्जी, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास की सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा। ये परियोजनाएँ जर्मन संगठन जीआईजेड द्वारा वित्त पोषित हैं और मध्यप्रदेश में एनआईसीटी इंदौर, महिला एवं बाल विकास विभाग और कृषि विभाग के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही हैं।

प्रदेश में कक्षा 5 और 8वीं की वार्षिक परीक्षा की समय-सारणी जारी

भोपाल (नप्र)। राज्य शिक्षा केन्द्र ने प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा की समय-सारणी जारी कर दी है। प्रदेश की समस्त शासकीय, मान्यता प्राप्त आशासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं के साथ डाईस कोड प्राप्त मदरसों में वार्षिक परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होंगी। सत्र 2024-25 की यह परीक्षाएँ 5 मार्च को समाप्त होंगी। परीक्षा की व्यवस्था को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आवश्यक निर्देश जारी किये हैं। कक्षा 5वीं की वार्षिक परीक्षा का पहला प्रश्न-पत्र 24 फरवरी को होगा और अंतिम प्रश्न-पत्र एक मार्च 2025 को होगा। प्रश्न-पत्र निर्धारित समय-सारणी के अनुसार दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक होगा। कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा का प्रश्न-पत्र 24 फरवरी को और अंतिम प्रश्न-पत्र 5 मार्च 2025 को होगा।

दिशा-निर्देश-स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राज्य शिक्षा केन्द्र ने परीक्षा के आयोजन को लेकर जिला कलेक्टर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। निर्देशों में कहा गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार निःशक्त विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय और लेखक की सुविधा प्रदान की जाये। परीक्षा की समय-सारणी की जानकारी शालाओं को भी भेजी गयी है।

एम्स भोपाल में एआई-आधारित कैंसर स्क्रीनिंग पर कार्यशाला का आयोजन

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में, एम्स भोपाल ने एआई के माध्यम से साइटोलॉजी स्क्रीनिंग - कैंसर स्क्रीनिंग और निदान में प्रगति पर एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यक्रम में बताया गया कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) केवल एक बूंद रक्त से कैंसर का पता लगा सकता है। यह अत्याधुनिक लिक्विड बायोप्सी तकनीक महंगे सीटी स्कैन या एमआरआई की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है, जिससे कैंसर का निदान तेजी से, अधिक सटीक और व्यापक रूप से सुलभ हो जाएगा। इस पहल का नेतृत्व प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने किया, जिन्होंने आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, यह क्रांतिकारी तकनीक कैंसर के निदान को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। यह बिना लक्षण वाले मरीजों में भी प्रारंभिक चरण में कैंसर का पता लगा सकती है। कैंसर की स्क्रीनिंग को तेज और अधिक सुलभ बनाकर, हम विशेष रूप से दूर-दराज और पिछड़े क्षेत्रों में अनगिनत जानें बचा सकते हैं। पारंपरिक विधियों में सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी महंगी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, जबकि यह एआई-संचालित तकनीक कैंसर का प्रारंभिक चरण में ही पता लगाने में सक्षम है, जिससे शीघ्र उपचार शुरू कर मरीज की जीवन बचाने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा, यह तकनीक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके कैंसर की सटीक पहचान करने में मदद करती है और आनुवंशिकी एवं जीवनशैली के आधार पर कैंसर के जोखिम का अनुमान भी लगाती है। यह कार्यशाला एम्स भोपाल के बायोकेमिस्ट्री और पैथोलॉजी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण और व्याख्यान दिए गए। इस कार्यशाला में प्रमुख योगदानकर्ताओं में प्रोफेसर जगत आर. कंवर (कार्यशाला प्रमुख), डॉ. सुखेस मुखर्जी (समन्वयक, बायोकेमिस्ट्री विभाग), प्रोफेसर वैशाली वाल्के, डॉ. जय चौरसिया और डॉ. शक्ति कुमार यादव (पैथोलॉजी विभाग) और डॉ. नीलम कोल्टे (बाहरी संसाधन विशेषज्ञ) शामिल थे। देशभर के 40 से अधिक पैथोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विशेषज्ञों ने इस कार्यशाला में भाग लिया, जिससे एआई-आधारित कैंसर निदान में बढ़ती रुचि स्पष्ट होती है। एआई पहले ही कैंसर निदान में अविश्वसनीय सटीकता साबित कर चुका है। गूगल का लिम्फ नोड असिस्टेंट ,आईबीएम का वॉटसन फ़ॉर ऑन्कोलॉजी और स्टैनफोर्ड का चेक्सनेट जैसी उन्नत एआई प्रणालियाँ अमेरिका और यूरोप में कैंसर निदान में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं। अब, एम्स भोपाल इस तकनीक को भारत ला रहा है ताकि अत्याधुनिक कैंसर निदान छोटे क्लीनिकों और ग्रामीण अस्पतालों में भी उपलब्ध कराया जा सके।

शादी में देरी से घट रही हिंदुओं की जन्मदर

वीएचपी के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे बोले- हर हिन्दू परिवार में दो-तीन बच्चे होने ही चाहिए

भोपाल (नप्र)। भोपाल पहुंचे विश्व हिन्दू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि, हिन्दुओं की घटती जन्मदर चिंता का विषय है। समाज को इन चुनौतियों पर विचार करना चाहिए। शुक्रवार को उन्होंने विश्व संवाद केन्द्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान परांडे ने कहा कि, हर हिन्दू परिवार में दो-तीन बच्चे होने ही चाहिए। इसको लेकर वीएचपी पूरे देश में जनजागरण करेगी।

मिलिंद परांडे ने कहा- विश्व हिन्दू परिषद की अभी एक अखिल भारतीय बैठक प्रयागराज महाकुंभ में हुई थी। देश भर के 1100 कार्यकर्ता सभी प्रांतों से आए थे। उसके पहले विभिन्न पंथ, संप्रदाय के साधु, संत, धर्माचार्य इस कार्यक्रम में जुटे थे। संतों की बैठकों में ये चर्चा हुई है।

एक करोड़ लोग विश्व हिन्दू परिषद के हितचिंतक बनेंगे- पूरे देश में वीएचपी द्वारा हितचिंतक अभियान चलाया जा रहा है, जिसे सदस्यता अभियान भी कहा जाता है। पिछले अभियान में देशभर से 72 लाख लोग वीएचपी से जुड़कर हितचिंतक बने थे। इस बार हमारा लक्ष्य पूरे देश में एक करोड़ हितचिंतक बनाने का है। देश के बाहर लगभग 30 देशो में वीएचपी का काम फैल चुका है। हिन्दू समाज के सामने कुछ चुनौतियां हैं। इसपर विचार हुआ। जैसे जनसंख्या में असंतुलन निर्माण हो रहा है। समाज को इन चुनौतियों पर विचार करना चाहिए। इसको लेकर वीएचपी पूरे देश में प्रयास करेगी। उसके तीन-चार कारण हैं।

पहला- ईसाई मिशनरी ताकतें हिन्दुओं के धर्मांतरण का काम कर रही है।

दूसरा- रेडिकल इस्लाम के माध्यम से लव जिहाद की घटनाएं और हिंसा के प्रकार बढ़ रहे हैं।

तीसरा- बांग्लादेश और म्यांमार से जो मुस्लिम घुसपैठ बढ़ रही है। ये भी बड़ा कारण है।

चौथा- हिन्दुओं की जन्म दर घट रही है।

प्रदेश की एकीकृत टाउनशिप नीति से शहरों का होगा नियोजित विकास

रियल एस्टेट विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये नीति में है प्रावधान

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की एकीकृत टाउनशिप नीति-2025 को मंजूरी दी गई है। नवीन नीति से प्रदेश में रियल एस्टेट विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित किये जाने के ठोस प्रयास किये जायेंगे। नीति के जरिये प्रदेश में किफायती आवास की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। नई टाउनशिप नीति से राज्य की सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता को पूरा किया जायेगा। प्रदेश में लैंड पूलिंग के माध्यम से सार्वजनिक और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा।

नई टाउनशिप नीति से प्रदेश को मिलेगा लाभ- विभाग द्वारा हाल ही में तैयार की गयी एकीकृत टाउनशिप नीति से रियल एस्टेट के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रदेश में अब भूमि मालिक लैंड पूलिंग से एक साथ आकर एकीकृत टाउनशिप विकसित कर सकेंगे। इससे राज्य में निवेश के अधिक अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अधोसंरचना सुविधाओं में तेजी से विकास होगा। नीति में वर्क सेंटर, जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक, कार्यालय, बाजार, आईटी, शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मनोरंजन आधारित गतिविधियाँ आदि के प्रावधान रखे गये हैं। इन सबके बढ़ने से राज्य की जीडीपी में वृद्धि होगी। वर्तमान में डेवलपर द्वारा छोटी-छोटी भूमियों पर कॉलोनियों का विकास किया जा रहा है, जिसके कारण नगर स्तर की अधोसंरचनाएँ विकसित नहीं हो पा रही हैं। तैयार की गयी नई नीति में ऐसे प्रावधान रखे गये हैं, जिससे शहर में सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना का विकास हो सकेगा। नागरिकों की सुविधा के लिये कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत पार्क और खुले स्थान का प्रावधान है, जिससे शहर में हरित क्षेत्र का विकास होगा। एकीकृत टाउनशिप नीति में कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लिये कुल आवासीय इकाइयों का न्यूनतम 15 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है। इस प्रावधान से राज्य के कमजोर एवं निम्न आय वर्ग की आवास की जरूरत पूरी होगी।

नीति के क्रियान्वयन के लिये साधिकार समिति- एकीकृत टाउनशिप नीति के क्रियान्वयन के लिये 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर के लिये प्रमुख सचिव शहरी विकास और आवास की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी है। ऐसे जिले जहाँ 5 लाख से कम आबादी वाले शहर हैं, वहाँ कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है। समिति में नगर तथा ग्राम निवेश, शहरी निकाय के आयुक्त, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है।

टाउनशिप परियोजनाओं के लिये प्रोत्साहन- नई नीति में निवेशकों को लैंड प्रोक्योरमेंट में सुविधा, सरकारी भूमि का कंट्रीब्यूशन, टीडीआर का लाभ और उच्चतम सीमा के लाभ का प्रावधान रखा गया है। नई नीति के जरिये कालोनी नियमों में रिलैक्सेशन, विकास योजना के भू-उपयोग में उपांतरण का प्रावधान रखा गया है। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी किफायती आवास के अतिरिक्त विकास पर अधिकतम 30 प्रतिशत और सामान्य आवास इकाइयों तक अतिरिक्त ईडब्ल्यू, एलआईजी अफोर्डेबल आवास के विकास पर प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त एफएआर प्रदान किया जायेगा। आवासीय कॉलोनियों में ऊर्जा के गैर परम्परागत उपयोग को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन के रूप में डेवलपर को अतिरिक्त एफएआर प्रदान किया जायेगा।

दुर्गाधाम मंदिर में विश्वकर्मा समाज का परिचय सम्मेलन कल

भोपाल। सर्व विश्वकर्मा समाज समिति मप्र भोपाल द्वारा 23 फरवरी दिन रविवार को दुर्गा धाम मंदिर अशोका गार्डन भोपाल में प्रातः 10.00 बजे से सायं काल 7.00 बजे तक युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें 400 बायोडाटा समिति को प्राप्त हुए हैं जिनका संकलन कर एक स्मारिका 'विश्वकर्मा दर्पण' का प्रकाशन भी किया गया है। स्मारिका का विमोचन महामंडलेश्वर भागवतानंद गिरि जी भगवान बापू के कर कमलों से संपन्न होगा। पूर्व में आयोजन लालघाटी स्थित गुफा मंदिर के मानस भवन में आयोजित किया जा रहा था लेकिन राजधानी में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के कारण सामाजिक बंधुओं को होने वाली परेशानी को देखते हुए दुर्गा धाम मंदिर सब्जी मंडी के पास अशोका गार्डन में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन स्थल पर सामाजिक ज्योतिषाचार्यों का कुंडली मिलान में सहयोग प्राप्त होगा तथा अभिभावकों को समस्या का त्वरित निदान प्राप्त होगा। मंच संचालन महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। प्रतिभागियों की अधिक संख्या को देखते हुए प्रातः 10:00 बजे भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना तथा गणेश वंदना और सरस्वती वंदना के साथ आयोजन का शुभारंभ होगा।

एसडीएम आकिब खान को किया जाए बर्खास्त

बिछिया विधायक के घर पर विवाद मामले में डीजीपी और सीएस से मिले पटवारी-सिंघार

भोपाल (नप्र)। बिछिया से कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा के भाई पर एफआईआर दर्ज होने के मामले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने डीजीपी कैलाश मकवाना और मुख्य सचिव अनुराग जैन से शुक्रवार को मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम आकिब खान को बर्खास्त करने की मांग की है।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भोपाल में पुलिस मुख्यालय में डीजीपी को पूरी घटना की जानकारी देते हुए एसडीएम आकिब खान को बर्खास्त करके आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की। उमंग सिंघार ने कहा कि, भाजपा के राज में आज मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। एक अधिकारी ने विधायक के परिजन से मारपीट की और उसपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उल्टा हमारे विधायक के परिजनों पर ही मामला दर्ज कर लिया गया।

ये कांग्रेस नेता डीजीपी से मिले- नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, सीडबल्यूसी मेम्बर कमलेश्वर पटेल, विधायक नारायण पट्टा, विधायक सचिन यादव, विधायक सुनील उइके, विधायक अभय मिश्रा, विधायक आरके दोगने, विधायक चैनसिंह बरकड़े, प्रदेश कांग्रेस महासचिव राजा बघेल, पूर्व विधायक नीरज दीक्षित, सुनील सर्राफ मौजूद रहे।

एम्स भोपाल में ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन टेस्टिंग, बेसिक टू एडवांस पर राष्ट्रीय स्तर वर्कशॉप का आयोजन

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और ब्लड बैंक विभाग ने 21 फरवरी 2025 को ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इंफेक्शन टेस्टिंग: बेसिक टू एडवांस पर एक सतत चिकित्सा शिक्षा कम कार्यशाला का सफल आयोजन किया। इस सीएमई को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें विभिन्न संस्थानों के 150 से अधिक चिकित्सा पेशेवरों ने भाग लिया। इस वर्कशॉप का उद्देश्य ट्रांसफ्यूजन-ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन टेस्टिंग की मौलिक अवधारणाओं और उन्नत डायग्नोस्टिक तकनीकों को गहराई से समझाना था।

सुरक्षा सुनिश्चित करना स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू है

इस वर्कशॉप के महत्व को रेखांकित करते हुए, प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने कहा- रक्त आधान (ब्लड ट्रांसफ्यूजन) की सुरक्षा सुनिश्चित करना स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और ट्रांसफ्यूजन-ट्रांसमिटेड संक्रमणों की सटीक जांच जटिलताओं को रोकने के लिए आवश्यक है। यह सीएमई-कम-वर्कशॉप एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा पेशेवरों को नवीनतम ज्ञान और व्यावहारिक कौशल से सुसज्जित करना है ताकि रक्त संक्रमण सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ाया जा सके।

इस वर्कशॉप में एमजीएम मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, एम्स नागपुर और एम्स भोपाल जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रख्यात अतिथि वक्ता ने अपने अनुभव और ज्ञान साझा किए। वैज्ञानिक सत्रों में टीटीआई टेस्टिंग में नवीनतम प्रगति पर चर्चा की गई, जबकि शाम के सत्र में ईएलआईएसए तकनीक और गुणवत्ता नियंत्रण उपायों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण प्रयोगशाला प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ।

इस सीएमई-कम-वर्कशॉप ने ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, प्रयोगशाला डायग्नोस्टिक्स और संक्रमण नियंत्रण से जुड़े स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षण और प्रशिक्षण अवसर प्रदान किया, जिससे रोगी देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार हुआ।

बैंक कर्मचारियों ने शुरू की हड़ताल की तैयारी, काम का बोझ बढ़ा, खाली पद भरो

भोपाल (नप्र)। बैंकिंग उद्योग में खाली लाखों पदों को भरने और 5 दिवसीय बैंक सप्ताह व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर देशभर के बैंक कर्मचारी 24-25 मार्च को हड़ताल करेंगे। भोपाल सहित मध्य प्रदेश में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले सप्ताह यूनियन के घटक संगठनों ने प्रदर्शन कर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। देशभर के 10 लाख बैंक कर्मचारी काम के बोझ से परेशान हैं। दरअसल बैंकिंग सेक्टर में लाखों पद खाली हैं। जिससे वर्तमान में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, उधर सरकार भर्ती करने को तैयार नहीं है। जिससे कर्मचारी नाराज हैं और हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं। यूनियन के वीके शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश की बैंकों में 50 हजार से अधिक कर्मचारी हैं, जो इस हड़ताल में शामिल होंगे। कर्मचारियों ने पेंशन से जुड़ी मांगें भी रखी हैं। इनमें पेंशन अपडेशन, पेंशन योजना में सुधार और डीए से जुड़ी परिभाषित लाभ पेंशन में शामिल होने का विकल्प देना प्रमुख हैं।

ऑर्केस्ट्रा डांसर से जंगल में गैंगरेप

साथी बोला- बदमाशों ने मुझे पीटा, युवती को घसीटा ; थाने में शिकायत की तो पुलिस ने भी पीटा

सिंगरौली (नप्र)। सिंगरौली में ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 22 साल की युवती एक कार्यक्रम में डांस करने के बाद साथी के साथ लौट रही थी। रास्ते में बाइक सवार छह बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। साथी के साथ मारपीट की। युवती को जंगल में घसीटकर ले गए।

आरोपी कार्यक्रम में मौजूद थे, वे डांस कर रही लड़कियों पर कमेंट कर रहे थे। इसके बाद पीछा करने लगे। घटना बुधवार देर रात की है। पीड़िता के साथी का आरोप है कि पुलिस ने जंगल में युवती को तलाश करने के बजाय उसे थाने में बिठाए रखा और मारपीट की।

वहीं, आरोपों को लेकर पुलिस कुछ भी नहीं कह रही है। गुरुवार को पीड़िता माड़ा पुलिस थाने पहुंची। रात करीब 10 बजे केस दर्ज किया गया। शुक्रवार को पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

सहेलियों के साथ डांस करने गई थी पीड़िता

पुलिस के मुताबिक शितूल गांव के रहने वाले देव कुमार शाह के घर बुधवार को छठी (बारहो संस्कार) कार्यक्रम था। इसके लिए सरई इलाके से ऑर्केस्ट्रा बुलाया गया था। इसमें अपनी बहन के साथ पीड़ित और अन्य युवती भी पहुंची थी। रात तकरीबन 10 बजे से 1 बजे तक डांस प्रोग्राम चला।

तीनों एक साथ रात करीब डेढ़ बजे चार साथियों के साथ चार बाइक से घर के लिए निकले। सभी आगे-पीछे चल रहे थे। दो बाइक सवार के साथ पीड़िता की बहन आगे निकल गई। तीसरी बाइक पर पीड़िता साथी के साथ, चौथी पर अन्य साथी पीछे आ रहे थे।

जबरन बाइक से उतारकर ले गए आरोपी- रजमिलान चौराहे के पास चार बाइक पर सवार 8 से 10 बदमाशों ने ओवरटेक कर रोक लिया। दोस्त ने विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट की। युवती को जबरन बाइक से उतारकर अपने साथ सखौहां शिव मंदिर के पास जंगल में ले गए। वहां छह लोगों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया। आरोपियों ने युवती का फोन भी छीन लिया।

दोस्त बोला- पुलिस आधे घंटे बाद पहुंची- युवती के साथी युवक ने बताया, आरोपियों के युवती को ले जाने के बाद चौथी बाइक पर बैठे साथी वहां पहुंचे। हमने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी। आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। युवती को तलाश करने के बजाय पुलिस हम तीनों को भदौरा चौकी ले गई। यहां से पुलिस ने साथी युवती को घर भेज दिया। हम दोनों लड़कों को बिठा लिया। पुलिस हमसे ये कहते हुए मारपीट करती रही कि हमने ही कुछ किया है।

लिफ्ट लेकर घर पहुंची पीड़िता- सुबह 6 बजे आरोपी युवती को उसी हालत में छोड़कर भाग गए। पीड़िता ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेकर घर पहुंची। उसने बड़ी बहन को पूरी घटना बताई। इसके बाद ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाले साथियों और बहन के साथ थाने पहुंची। दिनभर पड़ताल के बाद रात करीब 10 बजे पुलिस ने केस दर्ज किया। रात करीब 11 बजे के बाद मेडिकल परीक्षण किया गया।

पीड़ित की बड़ी बहन ऑर्केस्ट्रा की मालकिन- पीड़िता के साथी युवक ने बताया कि पीड़िता की बड़ी बहन ऑर्केस्ट्रा की संचालक है। उसी ने 3500 रुपए में बुकिंग ली थी। इनमें से तीन हजार रुपए मिल गए थे, जबकि 500 रुपए शुक्रवार को देना तय हुआ था।

युवक ने यह भी बताया कि आरोपी गांव में कार्यक्रम के दौरान भी डांस करने की जिद करते हुए बार-बार कमेंट कर रहे थे। आरोपी शितूल गांव से ही पीछा कर रहे थे। अनहोनी की आशंका के चलते हम लोग गांव के पास के पेट्रोल पंप में थोड़ी देर के लिए रुके भी थे। यहां भी आरोपी कमेंट करते रहे। एसपी मनीष खत्री ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। कोर्ट में युवती के बयान दर्ज होने के बाद ही ज्यादा कुछ बता पाएंगे।

मंदिरम्

45

श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठम, छतरपुर

छतरपुर मंदिर, जिसे श्री आद्या कात्यायनी शक्ति पीठम के नाम से भी जाना जाता है, भारत के दिल्ली में छतरपुर के डाउनटाउन क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर देवी कात्यायनी का सम्मान करता है। मंदिर परिसर 70 एकड़ के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यह नई दिल्ली के दक्षिण-पश्चिमी बाहरी इलाके में छतरपुर में स्थित है, और महरौली-गुड़गांव रोड से कुतुब मीनार से केवल 4 किलोमीटर दूर है। छतरपुर मंदिर, देवी दुर्गा के अवतार देवी कात्यायनी को समर्पित है, जिसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहा जाता है, जो 70 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर संगमरमर से बना है और इसमें द्रविड़ और नागर स्थापत्य शैली की झलक मिलती है। इसमें तीन परिसरों में 20 छोटे और बड़े मंदिर हैं, साथ ही एक कमरा भी है जिसमें चांदी की नक्काशीदार मेज, कुर्सियाँ, एक बिस्तर और एक ड्रेसिंग टेबल है। गर्भगृह में देवी की एक मूर्ति है, जिसे शेर पर सवार और तलवार चलाते हुए दिखाया गया है।

डुमना एयरपोर्ट पर यूएई से आए हाई-टेक फायर फाइटर

85 मीटर दूर से बुझाएंगे आग, 35 सेकंड में पकड़ेंगे 80 किमी/घंटा की रफ्तार

जबलपुर (नप्र)। हाल ही में 500 करोड़ रुपए की लागत से विस्तारित हुए डुमना एयरपोर्ट की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए आज दो मॉडर्न फायर फाइटर वाहन तैनात किए गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में निर्मित इन वाहनों की कुल कीमत 14.88 करोड़ रुपए है। ये वाहन 85 मीटर तक की दूरी से आग बुझाने की क्षमता रखते हैं और आपात स्थिति में एयरपोर्ट पर जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

एयरपोर्ट की सुरक्षा होगी और मजबूत- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लंबे समय बाद यह वाहन एयरपोर्ट को उपलब्ध कराए गए हैं। इनका उपयोग अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के मानकों के अनुसार किया जाएगा। प्रत्येक वाहन में 10,000 लीटर पानी, 1,300 लीटर फोम और 250 किलो शुष्क केमिकल पाउडर भंडारण की सुविधा है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सकेगी।

हाई-टेक फायर फाइटर की विशेषताएं

- प्रति मिनट 5000 लीटर पानी छोड़ने की क्षमता
- फोम और केमिकल की बौछार से आग बुझाने में सक्षम
- 39 टन भार क्षमता, 35 सेकेंड में 0 से 80 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने की क्षमता
- 110 किमी/घंटा की अधिकतम स्पीड
- 6×6 व्हील ड्राइव ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, जिससे तेजी से घटना स्थल पर पहुंच सकता है

पहले क्या था, अब क्या बदला?

अब तक डुमना एयरपोर्ट पर पुराने अग्निशमन वाहन थे, जिनकी क्षमता सीमित थी। इन नए वाहनों के आने से एयरपोर्ट की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह उन्नयन एयरपोर्ट को भविष्य में इंटरनेशनल उड़ानों के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अधिकारियों और यात्रियों की राय

विमानपत्तन निदेशक राजीव रत्न पांडेय ने कहा, ये वाहन एयरपोर्ट सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। किसी भी आपात स्थिति में ये तेजी से प्रतिक्रिया देंगे, जिससे यात्रियों और एयरक्राफ्ट की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

वहीं, एक यात्री अभिषेक वर्मा ने कहा, डुमना एयरपोर्ट लगातार आधुनिक हो रहा है, जो जबलपुर और पूरे महाकौशल क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है।

यूएई से नेफ्फको कंपनी ने किए तैयार

इन फायर फाइटर वाहनों को संयुक्त अरब अमीरात की नेशनल फायर फाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (नेफ्फको) द्वारा ग्लोबल टेंडर के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। जबलपुर एयरपोर्ट के सभी अग्निशमन कर्मियों को इन वाहनों के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया है।

फायर फाइटर वाहनों की तैनाती के दौरान जबलपुर एरोड्रम सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सांसद आशीष दुबे ने जबलपुर हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण के लिए भा.वि.प्रा. अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा, यह एयरपोर्ट को विश्वस्तरीय सुरक्षा सुविधाओं से लैस करने की दिशा में एक अहम कदम है।

रेप पीड़िता को लेकर अहम फैसला

24 सप्ताह तक का गर्भ होने पर पॉक्सो कोर्ट करेगी सुनवाई, जारी की एसओपी

जबलपुर (नप्र)। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रेप पीड़िताओं के गर्भपात को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इंदौर और जबलपुर बेंच की एकलपीठों द्वारा अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

24 सप्ताह तक के गर्भ के लिए तत्काल फैसला

अगर पीड़िता का गर्भ 24 सप्ताह या उससे कम अवधि का है, तो संबंधित जिले की पॉक्सो कोर्ट में मामला पेश करना होगा।

पॉक्सो कोर्ट तीन दिन के भीतर गर्भपात पर फैसला लेगी।

पीड़िता को बिना किसी आवेदन के मेडिकल बोर्ड भेजा जाएगा और परिजनों की अनुमति लेकर गर्भपात की प्रक्रिया करवाई जाएगी।

24 सप्ताह से अधिक के गर्भ पर हाईकोर्ट की अनुमति अनिवार्य

अगर गर्भ 24 सप्ताह से अधिक का है, तो जिला कोर्ट मामला हाईकोर्ट को भेजेगा।

हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए तेजी से मामले का निपटारा करेगी।

मेडिकल विशेषज्ञों की राय के आधार पर गर्भपात की अनुमति दी जाएगी।

डीएनए परीक्षण के लिए भ्रूण को सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

कोर्ट ने स्वत : संज्ञान लेकर लिया फैसला

हाल ही में जबलपुर और इंदौर बेंच की अलग-अलग गाइडलाइंस में विसंगति देखने को मिली थी। इस पर डिवीजन बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और उप-महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी व शासकीय अधिवक्ता अनुभव जैन की दलीलों को सुनने के बाद नई एसओपी जारी की।

डीएनए टेस्ट के लिए भ्रूण सुरक्षित रखना अनिवार्य

दोनों ही स्थितियों में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि डीएनए परीक्षण के लिए भ्रूण को सुरक्षित रखना जरूरी होगा, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जा सके।

छात्रों ने किया कक्षाओं का बहिष्कार

मैनिट में छात्रों और प्रबंधन के बीच खींचतान जारी

भोपाल (नप्र)। मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (मैनिट) में छात्रों और प्रबंधन के बीच रही खींचतान जारी रही। सीनियर छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया और हॉस्टल में रहे। छात्रों ने कहा कि जब तक डायरेक्टर डॉ. करुणेश शुक्ला उनसे बात नहीं करते, उनका पक्ष नहीं सुन लेते तब तक वे कक्षाओं में नहीं जाएंगे।

छात्रों ने डायरेक्टर पर आरोप लगाया कि वे उनके अभिभावकों को फोन लगाकर छात्र को संस्थान से निकालने की धमकी देते हैं और बेवजह का दबाव बनाते हैं। वे उनकी समस्याएं नहीं सुनते। अभिभावकों को यह कहा जाता है कि उनके बेटे का प्लेसमेंट नहीं होने दिया जाएगा। छात्रों ने कहा कि डायरेक्टर के इशारे पर ही पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। जो छात्र किसी घटना में शामिल भी नहीं थे पुलिस ने उन पर भी लाठियां चलाईं।

प्रबंधन ने कहा- कुछ छात्र सभी को धमकाकर कक्षा में जाने से रोक रहे

मैनिट प्रबंधन ने गुरुवार को यूजी और पीजी मिडिल सेमेस्टर एग्जाम (ऑड एंड इवन) फरवरी-2025 की परीक्षाएं आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दीं। यह निर्णय डायरेक्टर प्रो. शुक्ला की अध्यक्षता में हुई सभी डीन, एचओडी, सेंटर हेड्स, रजिस्ट्रार की बैठक में लिया गया। यह परीक्षाएं 24 फरवरी शुरू होनी थी। सभी विभागों की फैकल्टीज ने प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन किया है। प्रबंधन का कहना है कि कुछ छात्र मिलकर अन्य छात्रों पर कक्षाओं सहित अन्य एक्टिविटी में शामिल नहीं होने के लिए दवाब बना रहे हैं। उन्हें धमकाया जा रहा है। इस संबंध में उनके परिजनों को भी सूचना दी जा रही है। सीसीटीवी की मदद से छात्रों को चिह्नित किया जा रहा है। यह रैगिंग का मामला निकलता है तो दोषी छात्रों पर कार्रवाई की जाएगी।

जैविक खेती करने वालों को सोलर पम्प देगी सरकार : सीएम यादव

पांच लाख एकड़ एरिया में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें अफसर

आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भोपाल में दो दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 'एक जिला, एक उत्पाद' योजना के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने जैविक खेती से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के स्टॉल देखे और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और अनुभव जाने।

हार साल जैविक खेती में वृद्धि का टारगेट- कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमें खेती में केमिकल के उपयोग से बचना है। रसायन का अनावश्यक उपयोग जीवन शैली को बिगाड़ रहा है। उन्होंने जैविक और प्राकृतिक खेती में फर्क बताते हुए कहा कि जो अपने खाने के काम आए वह प्राकृतिक और जो विदेश के खाने के काम आए वह जैविक है। जैविक और प्राकृतिक खेती का बाजार हमारे प्रदेश में ही होना चाहिए। आने वाले समय में पांच लाख एकड़ में जैविक खेती का टारगेट रखना होगा। हर साल इसमें वृद्धि करना है।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले को सोलर पम्प देंगे ताकि बिजली संकट से उनको राहत मिले। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि कृषि आधारित राज्य में कृषि के लिए पूरे साल का प्लान बनाएं। कृषि आधारित उद्योगों पर सरकार फोकस करेगी। सरकार इसके लिए प्रोत्साहन देने का भी काम करेगी। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गौशालाओं का संचालन कराने पर सरकार काम कर रही है। महानगरों में कृषि आधारित व्यवस्था के आधार पर आस-पास के जिलों को जोड़ते हुए जैविक उत्पादों के मेले लगाए जाएं।

जीवों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए, इस पर चर्चा होगी: मंत्री कंसाना- कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री एदल सिंह कंसाना ने कहा कि बढ़ती हुई बीमारी पर रोक लगाने के लिए यह कार्यक्रम हो रहा है। जैविक खेती पर जोर देने के हो रही कार्यशाला में किसान और सभी जीवों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए, इस पर चर्चा होगी। जानलेवा बीमारियों को रोकने

के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इस पर जोर दे रहे हैं। खेती करने के मौजूदा दौर में रासायनिक उर्वरकों, खरपतवार नाशकों एवं कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के कारण भूमि एवं वातावरण में हानिकारक तत्वों की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण पर्यावरण, मिट्टी की उर्वरता तथा मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

जैविक खेती से विकास के लिए तैयार होगी रणनीति- कंसाना ने कहा कि कार्यशाला में जैविक कपास, फल एवं सब्जियां एवं अन्य फसलों के लिए जैविक खेती पद्धति एवं उत्पादों की मूल्य श्रृंखला विकसित करने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रदेश के विकास के लिए रणनीति तैयार की जायेगी।

कार्यशाला में केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, एफपीओ एवं जैविक खेती के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मंत्री कंसाना ने कहा कि प्रदेश के 33 जिलों में एक लाख एकड़ में जैविक खेती एमपी में की जा रही है। प्रदेश में जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए अशासकीय संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है।

किस जिले में क्या काम करना है, आज तय हो जाएगा: सेलवेंद्रन- कार्यशाला में सचिव किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग एम सेलवेंद्रन ने कहा कि आज से दो कार्यशाला शुरू हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे। आज और कल दो दिन जैविक खेती को एमपी में कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। किस जिले में किस प्रकार काम करना है, उसकी रूपरेखा कल तय हो जाएगी। इसके बाद इसी आधार पर काम शुरू होंगे। कार्यशाला में उद्यानिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन भी मौजूद रहे।

म.प्र.में मारी गईं छत्तीसगढ़ की 4 महिला नक्सली

आईजी बोले-बड़े कैडर के नक्सली इन्हें ढाल बनाते हैं और खुद बच के निकल जाते

जगदलपुर (नप्र)। मध्यप्रदेश के बालाघाट मुठभेड़ में 2 दिन पहले पुलिस ने जिन 4 महिला नक्सलियों को मार गिराया है वे छत्तीसगढ़ के बस्तर की रहने वाली थीं। इन पर छत्तीसगढ़, म.प्र.और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से कुल 62 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सभी हार्डकोर नक्सली थीं। एके 47, इंसास, एसएलआर जैसे राइफल चलाती थीं।

इस पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने कहा है कि, जो नक्सली मारे गए हैं उन्हें नक्सल संगठन के बड़े कैडर्स कुछ साल पहले लेकर गए थे। चारों महिलाएं बस्तर संभाग के ही जिलों की रहने वाली थीं। आईजी का कहना है कि, बस्तर के लोगों को गुमराह कर बड़े कैडर के नक्सली इन्हें मुठभेड़ में ढाल बनाते हैं और खुद बचकर निकल जाते हैं।

3 राज्यों की सीमा पर हुई मुठभेड़- दरअसल, मध्य प्रदेश के बालाघाट की सीमा महाराष्ट्र के गोंदिया जिले और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, खैरागढ़ और कवर्धा जिलों से लगती है। पुलिस के अनुसार मारी गईं नक्सली रंजीता, शीला, लक्खे मरावी और आशा 25 से 35 साल की थीं। वे मध्यप्रदेश के मंडला में कान्हा बाघ अभयारण्य और छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य के अलग-अलग एरिया कमेटी में सक्रिय थीं।

केबी डिवीजन के नाम से चर्चित इलाका- बालाघाट के आईजी संजय कुमार के मुताबिक, इस माओवादी इकाई को 'केबी' डिवीजन के नाम से भी जाना जाता था। केबी डिवीजन की कमांडर आशा थी जो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की रहने वाली थी। उसपर कुल 20 लाख रुपए का इनाम था। महाराष्ट्र में 12 लाख, छत्तीसगढ़ में 5 लाख और मध्यप्रदेश में 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था।

वहीं रंजीता, शीला और लक्खे मरावी पर 14-14 लाख का इनाम था। रंजीता उर्फ रामली आलमी छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की रहने वाली थी। इसपर महाराष्ट्र में 6 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ में 5 लाख रुपए और मध्यप्रदेश में 3 लाख रुपए का इनाम था। सरिता उर्फ शीला उर्फ पदम मूल रूप से छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की रहने वाली थी। महाराष्ट्र में 6 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ में 5 लाख रुपए और मध्यप्रदेश में तीन लाख रुपए का इनाम था। वहीं लक्खे मरावी भी सुकमा की रहने वाली थी। इस पर महाराष्ट्र में 6 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ में 5 लाख रुपए और मध्यप्रदेश में 3 लाख रुपए का इनाम था।

बेताल भूत नहीं, अत्यंत विद्वान था:मुख्यमंत्री

भोपाल में उद्योगपतियों से कहा- 4 लाख करोड़ से अधिक का होगा म.प्र.का बजट

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार का मार्च में पेश होने वाला बजट 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा। सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने में कोई कमी नहीं रखेगी। उद्योगपतियों की यह जिम्मेदारी है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले देश विदेश के उद्योगपतियों की मेहमान नवाजी का पूरा ध्यान रखें।

सीएम हाउस के समत्व भवन में उद्योगपतियों को प्रोत्साहन राशि वितरण करने के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विक्रमादित्य के शासन काल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपने शासन काल में प्रजा के सारे कर्ज खत्म कराए। भर्तृहरि गुफा के पास उज्जैन में ऋण मुक्तेश्वर महादेव हैं जो उनके दौर के महादेव हैं। विक्रमादित्य में यही खासियत थी कि वे इतना धन रखते थे कि न सिर्फ लोगों का कर्ज खत्म किया बल्कि उसके बाद की जिम्मेदारी भी संभाली।

अफसरों और योग्यता की कमी नहीं,परखने वालों की कमी है- मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि अफसरों की और योग्यता की कमी नहीं है बल्कि व्यक्ति को परखने की कमी है। उन्होंने अजीत डाभोल का उदाहरण करते हुए कहा कि डाभोल तो रिटायरमेंट के बाद घर बैठे थे और उन्हें सुरक्षा सलाहकार बनाकर उनकी योग्यता का लाभ लेने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सुयोग्य लोगों का संयोजन करने का काम पीएम मोदी कर रहे हैं।

4 लाख करोड़ रुपए का होगा एमपी का बजट- सीएम यादव ने कहा कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में

अलग-अलग राज्यों के बजट की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि एमपी सरकार का पिछली बार का बजट साढ़े तीन लाख करोड़ का रहा है जबकि साढ़े तीन लाख करोड़ इस साल खर्च हुए हैं।

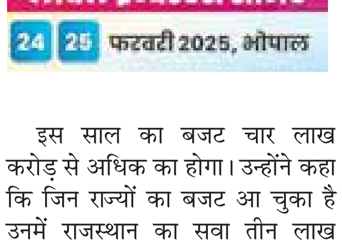

इस साल का बजट चार लाख करोड़ से अधिक का होगा। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों का बजट आ चुका है उनमें राजस्थान का सवा तीन लाख करोड़, हरियाणा का पौने दो लाख करोड़, उड़ीसा का बजट 1.90 लाख करोड़ रुपए का और यूपी का बजट 8 लाख दस हजार करोड़ का है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री चैतन्य काश्यप, विश्वास सारंग मौजूद थे।

यह भी बोले सीएम मोहन यादव- सरकार 200 प्रतिशत रिटर्न दे रही है। टूरिज्म सेक्टर में उद्योग लगाने पर 100 करोड़ में 40 करोड़ की मदद सरकार कर रही है। पिछड़े इलाकों में यही इन्वेस्ट करने पर 58 करोड़ रुपए दे रहे हैं। नए उद्योग लगना चाहिए और उन्हें मदद मिलना चाहिए लेकिन पुरानी इंडस्ट्री का भी ध्यान रखना होगा। यहां काम करने वालों की समस्या का निराकरण करने के लिए भी सरकार सोचती है। पुरानी इंडस्ट्री को नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ दिलाकर सस्ती बिजली देने का काम कर रहे हैं। सारे पिछड़े जिले जहां उद्योगों की संभावना है वहां भी काम कर रहे हैं। मल्टी स्टोरी के लिए भी पॉलिसी तय की है। इसके लिए भी सरकार छूट देने की तैयारी कर रही है।

1100 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 454 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। इसके पहले 400 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।